● वर्ष-4
● अंक-08
रायपुर, रविवार
18 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› कबीर बहिया के साथ शादी...

डॉक्टरों से की हड़ताल खत्म करने की अपील

नई दिल्ली। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में देशभर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर बुलाया गया है। देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे तक डॉक्टर हड़ताल पर रहने वाले है। राष्ट्रव्यापी काम बंद हड़ताल की शुरुआत 17 अगस्त सुबह छह बजे से हुई थी जो अब भी जारी है। इस हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी है ताकि किसी मरीज के परेशानी ना हो। इसके साथ ही कैजुअल्टी वॉर्ड भी

चालू हैं। हालांकि काम बंद हड़ताल के दौरान ओपीडी और सर्जरी विभाग में काम नहीं हो रहा है। इस काम बंद हड़ताल को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है।

इसी बीच फोर्डा, आईएमए और दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मुलाकात की है। ये मुलाकात डॉक्टर की स्ट्राइक के बीच में की गई है। इस दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर व अन्य मांगों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चर्चा हुई है।

जानकारी के मुताबिक एसोसिएशनों ने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता से संबंधित मांगें रखी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रतिनिधियों की मांगों को सुना है और उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। सभी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि सरकार स्थिति से भली-भांति परिचित है तथा उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है।

यह देखा गया कि 26 राज्य पहले ही अपने-अपने राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। एसोसिएशनों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर मंत्रालय ने उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित उपाय सुझाने हेतु एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने व्यापक जनहित में तथा डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंदोलनकारी डॉक्टरों से अपनी ड्यूटी पर लौटने का अनुरोध किया।

निर्भया की मां ने मांगा ममता से इस्तीफा

2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता निर्भया की मां आशा देवी ने शनिवार को कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वह स्थिति को संभालने में विफल रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बजाय, वह विरोध प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। आशा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के बजाय, ममता बनर्जी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।

40 से अधिक डॉक्टरों का किया तबादला

पश्चिम बंगाल सरकार ने आज देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच करीब 43 डॉक्टरों के तबादले का आदेश दिया है। यह विरोध प्रदर्शन आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले के कारण हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तबादलों के संबंध में 15 अगस्त (गुरुवार) को जारी सरकारी अधिसूचना के सामने आने के बाद, चिकित्सा बिरादरी और विपक्षी दलों ने दावा किया कि एक साथ कई डॉक्टरों का तबादला राज्य सरकार के प्रतिशोधात्मक रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इन 43 डॉक्टरों को मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए दंडित किया गया है।

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार

दुर्ग। बलौदाबाजार आगजनी-हिंसा मामले में नोटिस की तामीली नहीं करने पर बलौदाबाजार पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है. भिलाई विधायक पर बलौदाबाजार में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है. गिरफ्तारी के बाद विधायक समर्थकों के बीच झूमाझटकी हुई. आज लगभग 10 बजे से ही बलौदाबाज़ार पुलिस विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी. विधायक के गिरफ्तारी का विरोध करने सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए. ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कार के ऊपर चढ़कर सीना ठोककर और सतनाम का झंडा लहराया. इस दौरान संविधान की किताब भी लहराते हुए अपने समर्थकों का आभार जताया. साथ ही कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे.

जानिए पृष्ठभूमि

दरअसल, सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान 10 जून को बलौदाबाजार जिले के कलक्ट्रेट परिसर में आगजनी की घटना हुई थी. प्रदर्शनकारियों ने 150 से अधिक दो पहिया और 10 चार पहिया वाहनों को आग के हवाले किया था. कलेक्टर और एसपी कार्यालय में कई दस्तावेज जलकर खाक हुए थे.

कांग्रेस नेताओं को फंसाने की हो रही साजिश

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को फंसाने की साजिश हो रही है। पुलिस को राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। भाजपा से जुड़े एक भी नेता से पूछताछ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक सनम जांगड़े से पूछताछ क्यों नहीं हुई है। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। इस मामले में विधिक सलाह लेंगे और राजनीतिक कदम भी उठाएंगे।

प्रदेश में दो नई रेल लाइन परियोजना स्वीकृत

कोरबा से अम्बिकापुर और गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक दो नयी रेल लाइन का होगा अंतिम सर्वे

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में दो नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण की स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत होगा।

गौरतलब है कि रेल मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अंतर्गत 16 करोड़ 75 लाख रूपये लागत की कुल 670 किलोमीटर लंबी 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन दो रेल लाइन परियोजनाओं में से गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक 490 किलोमीटर की नई रेल लाइन के सर्वे को मिली स्वीकृति बस्तर के सर्वसमावेशी विकास की गति को कई गुना बढ़ाने वाली है। इसके सर्वे के लिए रेल मंत्रालय ने 12 करोड़ 25 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं। इससे बस्तर के सुदूर अंचल के लोग उच्च शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए रेलमार्ग से सीधे शहर से जुड़ेंगे। समूचा बस्तर क्षेत्र विकास के उच्च आयामों को छुएगा। वहीं कोरबा से अंबिकापुर तक 180 किलोमीटर की नई रेल लाइन के सर्वे को मिली स्वीकृति कोरबा और सरगुजा के सर्वसमावेशी विकास की गति को कई गुना बढ़ाने वाली है। इसके सर्वे के लिए रेल मंत्रालय ने 4 करोड़ 50 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में रेल सुविधा के क्षेत्र में इन दोनों सर्वे को मिली स्वीकृति क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, जिससे बस्तर और सरगुजा संभाग में रेल्वे सहित सभी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही इनसे हजारों-लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

दिव्य कला मेले में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं ऋण स्वीकृति पत्र किए गए वितरित

राजधानी में आयोजित दिव्य कला मेले में मुख्य अतिथि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री श्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारत सरकार की संस्था एलिम्को द्वारा दिव्य कला मेले में दिव्यांगजन को प्रोत्साहित करने के लिए टोकन के रूप में सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिसमे बलौदाबाजार जिला के 4 दिव्यांगजनों श्री संतोष यादव, श्री पुष्पराज पुरेना, श्री धनंजय देवांगन, सुश्री रामसीला पटेल को मोटराइज्ड ट्राई सायकल और रायपुर के श्री देवांश शर्मा को व्हील चेयर प्रदान किया गया।

प्रमुख समाचार

भाजपा चार राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा पा रही

जयपुर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार चार राज्यों में भी एक साथ चुनाव नहीं करा पा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार कई राज्यों और यहां तक कि वायनाड में भी उपचुनाव नहीं करा पा रही है। टोंक में पायलट ने संवाददाताओं से कहा, ''जो सरकार बोलती थी कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' हो वह चार राज्यों का चुनाव भी एक साथ नहीं करा सकती है या कराना नहीं चाहती है। वायनाड का लोकसभा सीट का उपचुनाव बाकी हैज न जाने किन कारणों से निर्वाचन आयोग ने सभी जगह चुनाव की घोषणा नहीं की।'' उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सचिन पायलट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और वहां भी 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलांयस' (इंडिया) गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। उदयपुर हिंसा पर पायलट ने शांति बनाए रखने की अपील है और कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

22 अगस्त को होगी जेपीसी की पहली बैठक

नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी, जिसके दौरान अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय 31 सदस्यीय पैनल को प्रस्तावित कानून के बारे में जानकारी देगा। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में विवादास्पद विधेयक पेश किए जाने के बाद हाल ही में संपन्न संसद सत्र के दौरान संयुक्त समिति का गठन किया गया था। वरिष्ठ भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को बहुदलीय पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। अपनी पहली बैठक में, पैनल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैठक में कानून और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले, मुस्लिम लीग ने लोकसभा या राज्यसभा में अपने पांच सांसदों में से किसी को भी पैनल में शामिल न किए जाने का विरोध किया था, जबकि दावा किया था कि समिति में एक सदस्य वाली पार्टियों को भी जगह मिली है।

दबाव में आकर उद्धव ने नहीं छोड़ी सीएम पद की दावेदारी

मुंबई। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सहयोगियों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की अपील का बचाव किया और इसके पीछे दबाव की राजनीति के दावों को खारिज कर दिया। शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने संवाददाताओं से कहा कि उद्धव ठाकरे ने दिल की उदारता दिखाई है। यह दबाव की राजनीति नहीं थी। इस रुख से महाराष्ट्र को फायदा होगा। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे को आगे आने की जरूरत नहीं है, वो 2019 में भी आगे नहीं आए, सबने मिलकर उन्हें सीएम बनाया था। अब 2024 की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने कभी नहीं कहा कि मैं सीएम बनूंगा, कल का भाषण सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस एनसीपी के पास कोई चेहरा है तो उसे सामने लाएं, उद्धव ठाकरे उस चेहरे का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता के दिल में हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर एमवीए सहयोगियों के बीच कोई मतभेद नहीं है।

पीओके के लिए रिजर्व रहेंगी 24 सीट, 90 सीटों पर होंगे चुनाव

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही जम्मू-कश्मीर में चुनाव के लिए 10 साल बाद सियासी माहौल गर्माने लगा है। विधानसभा के ये चुनाव वहां तीन चरणों में होंगे। ये चुनाव 18 सितंबर से 01 अक्टूबर तक होंगे। वोटिंग केवल 14 दिनों में हो जाएगी। हालांकि परिसीमन में राज्य में जितनी सीटें निर्धारित की गईं, उतने पर चुनाव नहीं होंगे। जम्मू-कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं लेकिन राज्य में विधानसभा सीटों के डिलीमिटेशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर ही होंगे। ये 24 सीटें पीओके यानि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण इनमें से केवल 90 सीटों के लिए चुनाव होना तय है। 114 सीटों में 24 सीटें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं, जिसका अर्थ है कि उन पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए, चुनाव के लिए उपलब्ध सीटों की प्रभावी संख्या 90 है। जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर संभाग में 47। राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।

अब तक अफ्रीका में 18,700 से ज़्यादा एमपॉक्स के मामले

नई दिल्ली। अफ्रीकी संघ की स्वास्थ्य एजेंसी ने शनिवार को बताया कि इस साल की शुरुआत से अब तक अफ्रीका में एमपॉक्स के कुल 18,737 संदिग्ध या पुष्ट मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,200 मामले सिर्फ़ एक हफ़्ते में सामने आए हैं। यह आँकड़ा वायरस के तीन प्रकारों से संबंधित है, जिनमें से एक नया ज़्यादा घातक और ज़्यादा संक्रामक क्लेड 1बी है, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया - जो एजेंसी का सबसे बड़ा अलर्ट है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने एक बयान में बताया कि आज तक 12 अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों से 3,101 पुष्ट और 15,636 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 541 मौतें हुई हैं - मृत्यु दर 2.89 प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो जहाँ सितंबर 2023 में पहली बार नए क्लेड 1ब्ल स्ट्रेन का पता चला था, ने एक हफ़्ते में 1,005 मामले (222 पुष्ट, 783 संदिग्ध) और 24 मौतें दर्ज की हैं। ब्रुक्ष्ट के सभी 26 प्रांतों में, जहाँ लगभग 100 मिलियन लोग रहते हैं, मामले सामने आए हैं।

नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली-चिमूर में भाजपा के लिए कठिन होगी चुनावी राह

लोक सभा क्षेत्र महाराष्ट्र के 48 संसदीय क्षेत्र में से एक है। यह नक्सल प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर नामदेव किरसन ने बीजेपी के अशोक नेते को मात देकर विजय हासिल की थी। 2002 में गठित परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद यह लोकसभा क्षेत्र 2008 से अस्तित्व में आया है। इस सीट पर 2009 में सर्वप्रथम चुनाव लड़ा गया था। चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले की तहसील चिमूर क्षेत्र को इस लोकसभा में शामिल किया गया है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से यह क्षेत्र जुड़ा हुआ है। गढ़चिरौली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र में कई आदिवासियों जातियों के लोग निवास करते हैं। वनीय क्षेत्र होने के कारण यहां तेंदूपत्ता और महुआ का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है।

यह लोकसभा क्षेत्र गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में विस्तारित है। जिसके अंतर्गत अमगांव, आरमोरी, गढ़चिरौली, अहिरी, ब्रह्मपुरी और चिमूर के विधान क्षेत्र आते हैं। जिसमें से चार विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में 6 में से तीन सीटें भारतीय जनता पार्टी, दो कांग्रेस और एक सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है। अमगांव, गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र की एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो गोंदिया जिले के अंतर्गत आती है। यह सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रहती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के सहसराम मारोती कोरोटे ने यह सीट बीजेपी के संजय हनुमंतराव पुरम से छीन ली थी।

महाराष्ट्र विधानसभा में 67 नंबर से जाने जानी वाली आरमोरी विधानसभा सीट गढ़चिरौली जिले के अंतर्गत ही आती है। यह निर्वाचन क्षेत्र भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य के गठन के साथ ही 1962 से अस्तित्व में आयी इस सीट पर एनसीपी को छोड़कर सभी दल जीत का स्वाद चख चुके हैं। वर्तमान में यहां से भारतीय जनता पार्टी के गजबे कृष्णा दामाजी विधायक हैं, जो लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं। उनसे पहले आनंदराव गंगाराम गेदम इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जो

कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2004 और 2009 का चुनाव जीते थे।

महाराष्ट्र राज्य के दूसरे विधानसभा चुनाव से अस्तित्व में आयी गढ़चिरौली विधानसभा सीट गढ़चिरौली जिले के अंतर्गत ही आती है। यह निर्वाचन क्षेत्र भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर अब तक शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। पिछले दो चुनावों से यहां भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर देवराव मडगुजी होली चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके पहले कांग्रेस के डॉ नामदेव दल्लूजी उसेंडी यहां से विधायक थे। इस लोक सभा क्षेत्र की अहिरी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक अन्य सीट है। यह निर्वाचन क्षेत्र भी पूरी तरह से गढ़चिरौली जिले के अंतर्गत ही आता है। जहां से वर्तमान में अजित पवार के गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आत्राम धर्मरावबाबा भगवंतराव विधायक हैं। भगवंत राव इससे पहले भी 1990 और 1999 से 2009 तक विधायक रह चुके हैं। यह उनका चौथा विधानसभा का कार्यकाल है। वे दो बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे हैं। 2023 में उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में भी जगह दी गई है।

गढ़चिरौली-चिमूर लोकसभा के अंतर्गत आने वाला ब्रह्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आता है। 1962 से अस्तित्व में आई इस सीट को पिछले चुनाव में कांग्रेस के विजय वड्डेटीवार ने जीता था। वे पिछले दो चुनावों से इस सीट पर जीते आ रहे हैं। उनके पहले यह सीट 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है। विधायक वड्डेटीवार महाराष्ट्र की वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। यह पद धारण करने वाले वे महाराष्ट्र के 27वें नेता हैं। इस पद पर रहने से पहले भी वे पूर्ववर्ती सरकारों के कई मंत्रालयों में बतौर मंत्री अपनी अलग-अलग जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ब्रह्मपुरी की सीट जीतने से पहले वे चिमूर विधानसभा से भी लगभग 10 साल तक विधायक रहे थे। कांग्रेस के दबदबे बाला चिमूर विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के तहत आता है। इस सीट पर 1962 से लेकर 1995 तक लगातार कांग्रेस चुनाव जीतती रही है। वर्तमान में यहां से भारतीय जनता पार्टी के बंटी भांगड़िया 10 साल से विधायक हैं। तो वहीं, उनसे पहले राज्य में विपक्ष के नेता विजय वड्डेटीवार पहले शिवसेना उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर 10 साल विधायक रहे थे। भांगड़िया विदर्भ क्षेत्र के सबसे अमीर जनप्रतिनिधियों में शामिल हैं। उन्हें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी भी समझा जाता है।

कांग्रेस के गौ सत्याग्रह से भड़के गौ रक्षक

■ कवर्धा थाने के सामने शुरू की हड़ताल

कवर्धा। कवर्धा सिटी कोतवाली के सामने गौ रक्षक, बजरंग दल और भाजयुमो कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौ रक्षकों की मांग है कि पशु क्रूरता करने वाले कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शुक्रवार को कवर्धा सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौ सत्याग्रह के नाम पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांग्रेस कर्यकर्ता छोटे वाहन में मवेशियों को ठूस ठूस कर ले गए। इनमें कई मवेशी बीमार भी थे।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर भर के मवेशियों को छोटे-छोटे वाहन में लादकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचने का काम किया। इसके बाद इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बहुत से मवेशी बीमार दिखे। साथ ही बेरहमी से गायों को पीटा भी गया। मवेशियों को वाहन से नीचे पटक दिया गया, जिससे हिन्दू और गौ रक्षक का मन आहत है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पशु क्रूरता की है। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई की मांग की है।

गौरक्षकों ने की कार्रवाई की मांग इस बारे में गौ रक्षक सागर साहू ने कहा कि, गौ संरक्षण के नाम पर जिस प्रकार कांग्रेस राजनीति चमकाने, फोटो खिंचवाने, के लिए मवेशियों पर अत्याचार किया है। यह पशुओं के साथ क्रूरता है। जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे।

इस बारे में कांग्रेस जिला अध्यक्ष होरी राम साहू ने कहा कि, सड़क पर जगह-जगह मवेशी के होने के कारण गौ माता चोटिल हो रही है। आम लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन के बाद बीमार मवेशी को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान वीडियो बनाकर दुष्प्रचार किया गया है।

कोतवाली प्रभारी लालजी सिन्हा ने कहा गौ रक्षकों की ओर से आवेदन देकर मांग की गई है कि कांग्रेसियों की ओर से विरोध प्रदर्शन के नाम पर मवेशियों से क्रूरता पूर्वक सलूक किया गया। जिससे मवेशी बीमार हुए हैं और घायल हुए हैं। इस मामले में आवेदन लिया गया है। केस की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार का पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौ सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि साय सरकार छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को बंद कर रही है।

समेली पंचायत के पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपित गिरफ्तार

दंतेवाड़ा। थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माड़ेदा में समेली पंचायत के पूर्व सरपंच भीमा मंडावी पिता स्व. दामा मंडावी उम्र 35 वर्ष पर जान लेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों ग्राम पोटाली सरपंच पति लखमा मंडावी, राहुल पोडियामी, मंगल सोड़ी एवं सुक्का मंडावी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उक्त चारो आरोपियों ने पूछताछ में अपराध करना स्वीकार करते हुए बताया कि पीड़ित भीमा मंडावी को पोटाली गांव के जोगाराम पोडियामी की हत्या का क़सूरवार मानते हुए बदला लेने की नीयत से हमला करना स्वीकार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना दौरान पीड़ित भीमा मंडावी अपने भाई गुज्जा मंडावी के साथ ग्राम माड़ेदा स्थित हॉलर मिल में काम कर रहे थे। इसी दौरान पोटाली गांव से राहुल पोडियामी, लखमा मंडावी, सुक्का मंडावी और मंगल सोड़ी ने हमारे गांव के सियान जोगा पोडियम को तुम्हीं मरवाये हो, बोलकर हमला कर दिया और भीमा मंडावी को हाथ, गर्दन, जांघ, सीने में धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। मौक़े पर मौजूद गुज्जा मंडावी द्वारा बीच बचाव करने पर आरोपियों द्वारा गुज्जा के साथ भी मारपीट की गई इस दौरान मौक़ा पाकर भीमा घायल अवस्था में ही मौक़े से घर की ओर भागने में सफल रहा। मौक़े से आरोपीगण बीच बचाव कर रहे गुज्जा को जबरन बाइक में बिठाकर पोटाली की ओर ले जाने लगे। जैसे ही बाइक थाना अरनपुर के पास पहुची तो गुज्जा जान बचाने के लिए बाइक से कूद गया और थाने के गेट की ओर भागा, आरोपी पोटाली की ओर भाग निकले। थाने में सूचना मिलते ही तत्काल अरनपुर थाना प्रभारी थाना बल के साथ मौक़े के लिए रवाना हुए और मौक़े से लखमा मंडावी, सुक्का मंडावी, मंगल सोड़ी को हिरासत में लिया जबकि राहुल पोडियामी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 4 आरोपियों नामज़द आरोपियों 1. सुकदेव पोडियामी पिता स्व जोगाराम पोडियामी उम्र 20 वर्ष निवासी पोटाली धुरवापारा थाना अरनपुर 2. लखमा मंडावी पिता स्व केशा मंडावी उम्र 45 वर्ष निवासी पोटाली धुरवापारा थाना अरनपुर 3. सुक्का मंडावी पिता स्व पांडुराम मंडावी उम्र 35 वर्ष निवासी पोटाली धुरवापारा थाना अरनपुर 4. मंगल सोड़ी पिता स्व आयता सोड़ी उम्र 35 वर्ष निवासी पोटाली धुरवापारा थाना अरनपुर के विरुद्ध थाना अरनपुर में अपराध क्रमांक 12/2024 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2),191(2),141(1),109(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर कायर्वाही उपरांत आज शनिवार को आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड में लिया गया।

हाथियों के आतंक ने ली जान

■ मृतिका के घर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया

कोरबा। हरदी बाजार ग्राम रलिया में कुछ दिनों पहले हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई थी। मृतिका का नाम गायत्री देवी राठौर था, जो रलिया के व्यावसायिक रामचरण राठौर की भाभी और अमित राठौर की माता थी। आंगन बाड़ी के कार्यकर्ता थीं।

मृतक के परिवार से दुख के घड़ी में दुख व्यक्त करने शुक्रवार की रात उनके निवास स्थान पर छत्तीसगढ़ शासन के नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरण दास महंत पहुंचे। उनके साथ पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ,पूर्व विधायक राज्य मंत्री पुरुषोत्तम कंवर और महिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रभा सिंह तंवर के द्वारा हाथी प्रभावित मृतक के परिवार से भेंट की। दुख व्यक्त कर ढांढस बांधा। इस दौरान कांग्रेस के और अन्य कार्यकर्ता ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

डॉक्टर चरण दास महंत ने कहा कि दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। वहीं घटनाक्रम की जानकारी ली गई। दंतैल हाथी अब तक तीन महिलाओं को मौत के घाट उतार चुका है। रलिया के बाद खैरभवना में दो महिलाओं के मौत के घाट उतारा था। उसके बाद जांजगीर चांपा जिले कोरबा के सीमा से लगी खिसोरा जंगल में पिछले तीन दिनों से डेरा डाला हुआ है। जहां हाथी अब तक जंगल से बाहर नहीं निकला है।

हाथी की निगरानी के लिए तीन जिले के वनकर्मी लगे हुए हैं। कटघोरा वन मंडल, जांजगीर चांपा वन मंडल, बिलासपुर वन मंडल के कर्मचारी तैनात हैं। कटघोरा डीएफओ निशांत कुमार झा ने बताया कि हाथी किशोर जंगल में अभी भी विचरण कर रहा है। इसके लिए आसपास गांव में मुनादी कराई जा रही है। वहीं ग्रामीणों को जंगल जाने से रोका जा रहा है।

खैरागढ़ में स्वाइन फ्लू, छुईखदान सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान नहीं चला पता

निजी अस्पताल में जांच करने पर स्वाइन फ्लू की पुष्टि

राजनांदगांव। खैरागढ़ में स्वाइन फ्लू का मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जिले में एक मरीज स्वाइन फ्लू पॉजीटिव पाया गया है। जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। छुईखदान सरकारी अस्पताल के स्टाफ और मरीजों की भी जांच कराई गई है।

खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के छुईखदान में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। छुईखदान के रहने वाला एक व्यक्ति 7-8 दिनों से सर्दी खांसी और बुखार से बीमार था। छुईखदान शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ठीक नहीं होने पर परिजनों ने राजनांदगांव के निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया। जहां जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई।

स्वाइन फ्लू का मरीज मिलने के बाद जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर मनीष बघेल ने बताया मरीज के स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद छुईखदान सरकारी अस्पताल के स्टाफ और मरीजों की भी जांच कराई गई है। इसके साथ ही स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आए व्यक्ति के परिजनों और क्षेत्र के लोगों का मेडिकल टेस्ट भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। वार्ड के सभी लोगों की जांच कर सैंपल भेजा गया है। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सभी प्रयास किया जा रहे हैं।स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और सर्दी खांसी बुखार होने पर तुरंत अस्पताल में संपर्क करने की अपील की जा रही है।

आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में तीन महिलाओं की मौत हो गई है और सात अन्य घायल हो गईं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जिले के पत्थलगांव और बागबहार थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने की दो घटनाओं में तीन महिलाओं श्रद्धा यादव (35), राखी पैंकरा (20) और अखियारो मिंज (40) की मौत हो गई।

अधिकारियों के मुताबिक, पत्थलगांव क्षेत्र के अंतर्गत चंदागढ़ गांव में शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे नौ महिलाएं खेत में काम करने गई थीं, तभी वहां अचानक बारिश होने लगी और तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में दो महिलाओं श्रद्धा और राखी की मौत हो गई तथा सात अन्य घायल हो गईं। उन्होंने बताया कि जब अन्य ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली, तब प्रभावितों को अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों के अनुसार, इसी तरह की एक अन्य घटना में बागबहार क्षेत्र के अंतर्गत कुरकुट नाले के करीब खेत में काम करने के दौरान अखियारो मिंज नामक महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गई।

उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जशपुर जिले में मानसून के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है। जिले में इन घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है।

सीएम साय ने जताया दुःख इलाज के दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानसून कमजोर हो गया है, लेकिन सरगुजा संभाग में रोजाना गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। वहीं जशपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन महिलाओं की मौत हो गई। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। उन्होंने घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल्द स्वस्थ होने की कामना किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट लिखा कि जशपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन महिलाओं की मृत्यु और कई महिलाओं के घायल होने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन द्वारा घायल महिलाओं को त्वरित इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रशासन को बेहतर इलाज की व्यवस्था करने और अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। ईश्वर से दिवंगत महिलाओं की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

गृहमंत्री ने हिड़मा के गांव पूवर्ती पहुंचकर ग्रामीणों से की चर्चा

सुकमा। गृहमंत्री विजय शर्मा नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव पूवर्ती पहुंचकर बाइक से इलाके का दौरा किया। लोगों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके गांव में सड़कें बनेंगी, अस्पताल, स्कूल खोले जाएंगे। घर तक एंबुलेंस पहुंचेगी। राज्य गठन के बाद विजय शर्मा सरकार के पहले गृहमंत्री हैं जो इस इलाके में पहुंचे हैं। इस दौरान गृहमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीणों से भेंटकर कहा कि उन्हें रोजगार मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। गांवों में सड़कें बनेंगी तो एंबुलेंस सीधे घर तक पहुंच जाएगी। अस्पताल की सुविधा मिलेगी, इसके लिए इलाके में शांति चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। पूर्वती गांव में गृहमंत्री अलग-अलग पारा में जाकर लोगों से मिले। नक्सल प्रभावित इलाके की जमीनी स्थिति जानी। इसके उपरांत वे कैंप में तैनात जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया।

हत्या का फरार एक आरोपी नक्सली गिरफ्तार

सुकमा। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जिला पुलिस बल और 219 वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी ने एरिया डोमिनेशन अभियान पर रवाना हुए थे। अभियन के दैरान थाना भेज्जी क्षेत्र से कोत्ताचेरु-भण्डारपदर के मध्य जंगल से हत्या के एक मामले में वांछित फरार एक नक्सली कवासी हिड़मा निवासी ग्राम भण्डारपदर, थाना भेज्जी, जिला सुकमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कवासी हिड़मा और उसके नक्सली साथियों पर भण्डारपदर में विद्युत कार्य के लिए गए पोडियाम जोगा की हत्या का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद थाना भेज्जी में कार्यवाही उपरांत आज नक्सली कवासी हिड़मा को न्यायालय में पेश कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया। इस कार्यवाही में 219 वाहिनी सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल का योगदान रहा, अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है।

राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए दिल्ली जाएंगी केजीबीवी की छात्रा

गरियाबंद। रक्षाबंधन के अवसर पर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 19 अगस्त को भेंट-मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ से देवभाग के कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय देवभोग (केजीबीवी) की छात्रा चेतना सोनाराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने जाएंगी। इस अद्वितीय अवसर के लिए केजीबीवी देवभोग ने चेतना को शुभकामनाएं दी हैं और शासन व प्रशासन को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। विद्यालय की अधीक्षिका उषा वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण अवसर को लेकर पूरे संस्था की तरफ से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के और शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में संबंधित सभी अधिकारियों-सचिव, संयुक्त सचिव, राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर, संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर, जिला कलेक्टर दीपक अग्रवाल और जिला परियोजना समन्वयक खेलसिंह नायक को धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित किया है।

किराएदारों की जानकारी नहीं देने पर होगी कार्रवाई

जगदलपुर। बस्तर जिले में लगातार बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए अब बस्तर पुलिस ने नया पैंतरा आजमाया है।बस्तर पुलिस जिले में किराए पर रहने वालों की जानकारी लेने में जुट गई हैं। बस्तर पुलिस ने यह कार्रवाई जगदलपुर शहर से शुरू की है। मकान मालिकों से किराएदारों की जानकारी मांगी है। मकान मालिक जानकारी नहीं देते हैं तो उनके पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। पुलिस लगातार अलग अलग मोहल्लों में जाकर ऐसे मकान मालिकों से जानकारी ले रही है, जिन्होंने अपने घर किराए पर दिए हुए हैं। शहर के कालीपुर अटल आवास, सनसिटी अटल आवास, गंगा मुंडा, नया मुंडा, आड़ावाल, शांतिनगर के अलग अलग घरों में पुलिसकर्मी पहुंचे और जानकारी ली। बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया जिले में रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो भी किराएदार बाहर से आकर रह रहे हैं, उनकी जानकारी ली जा रही है। सभी मकान मालिकों से अपील करते हुए कहा गया है कि जो भी किराएदार उनको घरों में रह रहे हैं।

जर्जर सड़क व घाट को लेकर चक्काजाम आज

कोंड़ागांव। केशकाल शहर की सड़क और घाट की जर्जर स्थिति से आक्रोशित नगरवासियों ने 18 अगस्त को केशकाल शहर में चक्काजाम की घोषणा के बाद इस मामले को लेकर आज एसडीएम अंकित चौहान की अध्यक्षता में विशेष बैठक रखी गई थी। इस बैठक में एसडीओपी भूपत सिंह, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के एसडीओ घनश्याम साहू, थाना प्रभारी विकास बघेल के साथ-साथ स्थानीय नगरवासी भी शामिल हुए। बैठक में केशकाल शहर की सड़क को लेकर चर्चा हुई जिसमें कुछ अहम निर्णय लिए गए जिसमें एनएच के एसडीओ घनश्याम साहू ने आश्वस्त किया है कि आगामी 20 सितंबर से सड़क की मरम्मत एवं घाटी के नवीनीकरण का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। धूल की समस्या से निजात दिलाने के लिए एनएच विभाग शहर में प्रतिदिन 5-6 बार पानी डलवाया जाएगा। यदि एनएच विभाग दिन में 5 बार पानी नहीं डलवाता है तो एसडीएम अंकित चौहान एनएच विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। बता दें कि यह बैठक लगभग 1 घण्टे तक चली।

अब रेलवे लाइन से जुड़ेगा बीजापुर, केंद्र ने दी कोरबा-अंबिकापुर रेलवे लाइन को मंजूरी

बिलासपुर। कोरबा से अंबिकापुर और गढ़चिरौली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे को रेल मंत्रालय से मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कोरबा से अम्बिकापुर (180 कि.मी.) एवं गढ़चिरोली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) (490 कि.मी.) नई रेल लाइन निर्माण के लिए फाइनल सर्वे व डीपीआर तैयार करने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा 16.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है ।

कोरबा से अंबिकापुर नई रेल लाइन छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोडने तथा गढ़चिरौली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) नई रेल लाइन महाराष्ट्र एवं छतीसगढ़ के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं ओडिशा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ भी बेहतर रेल कनेक्टिविटी स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई जा रही हैं । कोरबा से अंबिकापुर रेल लाइन को मंजूरी मिलने से छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित दो प्रमुख शहरों ऊर्जा नगरी कोरबा एवं सरगुजा जिला का मुख्यालय अम्बिकापुर शहर के साथ ही साथ इसके आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी

बनाएगी, जिससे यात्री यातायात व माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा । गढ़चिरौली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) नई रेल लाइन महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सूदूर क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे इन क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहन के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर भी उपलब्ध होंगे ।

इन दोनों परियोजनाओं के फाइनल सर्वे की मंजूरी का मतलब है कि अब इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण का काम जल्द ही शुरू होगा, जिसके आधार पर आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी । यह कदम क्षेत्रीय विकास और समग्र आर्थिक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकेगा ।

कोरबा- अंबिकापुर और गढ़चिरौली से बचेली (व्हाया-बीजापुर) नई रेल लाइन के लिए फाइनल सर्वे की मंजूरी पर रेलमंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। छत्तीसगढ़ में इस समय 37,018 करोड़ रुपये की लागत से 2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। जब रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा हो और उसी समय नई पटरी का निर्माण, नए स्टेशन का निर्माण, रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास एवं यार्ड रिमॉडलिंग जैसे रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विभिन्न कार्य किए जाते हैं, तो ट्रेनों के सुगम परिचालन में कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। इसी के चलते कई बार ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ता है। लेकिन हम संकल्पित हैं कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द विश्वस्तरीय रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करेंगे और राज्य के लोगों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे एवं अधिक से अधिक ट्रेनें चलाएंगे।

रेलमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राज्य के उपमुख्यमंत्री अरुण साव और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने राज्य में रेलवे से संबंधित कई परियोजनाओं की मांग की थी। इन्हीं में से आज 670 किलोमीटर की दो नई रेल लाइन परियोजनाओं की डीपीआर (16.75 करोड़ रुपये) को स्वीकृत दी गई है। इनमें 180 किलोमीटर लंबी कोरबा एवं अंबिकापुर नई रेल लाइन परियोजना की डीपीआर (4.5 करोड़ रुपये) एवं 490 किलोमीटर लंबी गढ़चिरौली-बचेली वाया बीजापुर नई रेल लाइन परियोजना की डीपीआर (12.25 करोड़ रुपये) शामिल है।

भारतीय रेल छत्तीसगढ़ राज्य में रेल नेटवर्क का जाल बिछाने के लिए कृत संकल्पित है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए 6,922 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। जो कि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान छत्तीसगढ़ को प्रति वर्ष आवंटित किए जाने वाले औसतन 311 करोड रुपये के बजट से लगभग 22 गुना अधिक है।

नई रेल लाईन से बीजापुर सहित बस्तर तेज़ी से विकास की पटरी पर दौड़ेगा : कश्यप

बीजापुर। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में दो नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दी है। नई रेल लाईन की मंजूरी पर हर्ष व्यक्त करते हुए बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि अब बीजापुर सहित बस्तर तेज़ी से विकास की पटरी पर दौड़ेगा। इनमें से एक नई रेलवे लाइन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से छत्तीसगढ़ के बचेली तक, जो बीजापुर से होकर गुज़रेगी, 490 किलोमीटर की होगी। दूसरी 180 किलोमीटर की रेलवे लाइन कोरबा से अंबिकापुर के बीच शुरू होगी, जिसके सर्वे और डीपीआर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 16.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। नई रेल लाईन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए गंभीरता से सोचने वाले देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।

कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण देव एवं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य मंत्री व नेताओं के द्वारा भी छत्तीसगढ़ सहित बस्तर के विकास व रेल लाइन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को समय-समय पर अवगत करवाया जाता रहा है। नई रेल लाईन अब बस्तर के एक छोर से महाराष्ट्र ,तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, ओडिसा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ेगी।

संक्षिप्त समाचार

रायपुर दक्षिण से पार्टी जिसे टिकट देगी उसका सहयोग करूंगा : बृजमोहन

रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट खाली हो गई है। इस सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस को ह्हह्क के प्रत्याशी का समर्थन कर देना चाहिए। जमानत जब्त कराने के लिए चुनाव लड़ने से कोई लाभ नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल किसके साथ इस सवाल पर उन्होंने कहा, ह्हह्क जिसे टिकट देगी उसका सहयोग करूंगा। कांग्रेस में उठापटक पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, अब तक तो लगता था प्रदेश में चार-पांच कांग्रेस है। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम की कांग्रेस थी। अमितेश शुक्ल, अमरजीत भगत भी जागृत हो गए हैं। चरणदास महंत की एक अलग कांग्रेस चल रही है। पता नहीं प्रदेश में कितनी कांग्रेस चल रही है। सब मिलकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इससे सिर्फ प्रदेश को नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होगा।

रक्षाबंधन पर सामान्य अवकाश की जगह सार्वजनिक अवकाश घोषित

रायपुर। इस बार भाई-बहन का त्योहार रक्षाबंधन पहले से ज्यादा खुशियां लेकर आया है। इस बार छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन पर छुट्टी रहेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार 19 अगस्त रक्षाबंधन पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने सावन सोमवार के अंतिम दिन यानी 19 अगस्त 2024 सोमवार को 'रक्षाबंधन' पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व में सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। नवीन अधिसूचना के अनुसार अब 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन पर्व पर छत्तीसगढ़ में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 अक्टूबर 2023 जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है।

दिव्य कला मेला में मुख्यमंत्री को पैरा शिल्प से निर्मित पोर्ट्रेट भेंट की गई

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री साय को राजधानी

रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में आयोजित दिव्य कला मेला में कलाकार सुश्री हीरा धृतलहरे ने अपने हाथों से बनाई पैरा शिल्प पोर्टेट भेंट की। सुश्री हीरा की भेंट पाकर मुख्यमंत्री ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने सुश्री हीरा से कहा कि उनके पास पैरा शिल्प स्केच बनाने का अनूठा हुनर है और खूब अभ्यास कर इसको निखारना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, उसकी बारीकियाँ पता चलती है। लगातार प्रैक्टिस करके वो एक अच्छी शिल्पी बनकर देश-दुनिया में अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकती है।

जगन्नाथ मंदिर में 2100 राखियां बांधकर मनाया जाएगा रक्षाबंधन : पुरन्दर

रायपुर। उत्तर विधानसभा के विधायक एवं जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष पुरन्दर मिश्रा ने आज एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि रक्षाबंधन के पर्व को इस बार भगवान जगन्नाथ से विशेष रूप से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहां भाई-बहन की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इसी उपलक्ष्य में 18 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में विशेष आयोजन रखा गया है, जिसमें क्षेत्र की बहनों द्वारा भगवान जगन्नाथ को 2100 राखियां बांधी जाएंगी। मिश्रा ने बताया कि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है।

पॉवर कंपनी में चेयरमेन दयानंद ने किया ध्वजारोहण

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में पॉवर कंपनी के चेयरमेन श्री पी. दयानंद (आई.ए.एस.) ने विद्युत सेवा प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में विद्युत कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए पॉवर कंपनीज की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी पॉवर जनरेशन कंपनी ने विगत वर्ष 84.4 प्रतिशत पीएलएफ. तथा 21 हजार मिलियन से अधिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा है। यह गौरव राज्य को तथा हमारे कंपनी को पहली बार हासिल हुआ है। बिजली घरों में सबसे कम ऑइल और ऑक्जलरी खपत के नये कीर्तिमान बनाया गया है। बिजली उत्पादन के नये प्रयासों की जानकारी विस्तार से दी। पारेषण क्षमता की विस्तार और मजबूती के लिए विद्युत कर्मियों युद्ध स्तर पर तेजी से काम कर रहे है। वर्तमान में 3 हजार 6 सौ मेगावाट पारेषण की क्षमता अर्जित की गई है। पारेषण कंपनी द्वारा विगत 7 माह के अल्प समय में अति उच्चदाब के 2 उपकेन्द्र, 12 नये ट्रांसफॉर्मर के ऊर्जीकरण का कार्य सम्पन्न हुआ। 203 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन बिछाई गई। विगत 7 माह में उच्चदाब के 176 तथा निम्नदाब के 1 लाख 1 हजार 4 सौ उपभोक्ता की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सात माह के भीतर 33/11 केवी. क्षमता के 98 उपकेन्द्र तथा 45 उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि, 47 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं। इसी तरह मानव संसाधन विभाग द्वारा कैशलेस हेल्थ स्कीम को बेहतर बनाते हुए अब 5 सौ अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया है। प्रदेश से बाहर सीजीएचएस. दर से इलाज की सुविधा दी जाएगी। अन्य नई सुविधा में जैसे- रोबोटिक और आधुनिक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, प्रीवेंटिव कामन नि:शुल्क ऑनलाईन परामर्श दी जाएगी और महिलाओं कर्मियों के लिए अपने सास-ससुर अथवा माता-पिता दोनों में से किसी एक को चयनित करने का विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने कंपनीज के कर्मियों की प्रशंसा करते हुए बधाई दी। समारोह में ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री आर.के.शुक्ला, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर एवं जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एस.के.कटियार, कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री अशोक कुमार वर्मा, अति. मुख्य अभियंता विनोद कुमार अग्रवाल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी विंग कमाण्डर श्री ए.के.श्रीनिवास राव सहित एवं अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु अधिकारी एवं कर्मचारीगण को अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

साथ ही सतर्कता एवं सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सर्वश्री आर.के.साहू, सुरक्षा निरीक्षक प्रभुशरण सिंह एवं बैन्ड दल के ताराचंद बेन के नेतृत्व में परेड की प्रस्तुति दी गई। समारोह का संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्र ने किया।

कमिश्नर ने वीडियो कांफ्रेसिंग से ली संभाग के कलेक्टर की बैठक

रायपुर। रायपुर संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संभाग के कलेक्टर की बैठक ली। श्री कावरे ने कहा कि निर्धारित समय पर कर्मचारी शासकीय कार्यालय में पहुंचे। साथ ही कार्यालय निर्धारित समय में खुलें। सभी कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारियों के नाम की पट्टिकाएं अवश्य लगाएं। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सभी संभाग के अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेंगे।

सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मॉडल बने लोरमी: साव

■ उप मुख्यमंत्री ने रायपुर में लोरमी के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर में लोरमी के विकासखण्ड और तहसील स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि लोरमी के विकास और वहां के नागरिकों को खुशहाल बनाने के लिए मैं भी आपकी टीम का हिस्सा हूं। हम सब मिलकर क्षेत्र का तेजी से विकास करेंगे और जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लोरमी प्रदेश में नज़ीर बने, ऐसा काम हम सबको मिलकर करना है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि हम सबको मिलकर लोरमी की समस्याओं को दूर करना है। क्षेत्रवासियों को सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोरमी के लोगों के लिए नई कार्ययोजनाएं तैयार करें और उन्हें गंभीरता से अमलीजामा पहनाएं। उन्होंने लोक सेवक के तौर पर नागरिकों से अच्छा व्यवहार रखने और उनकी समस्याओं का तत्परता से निराकरण करने को कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की के वे अच्छे कार्यों से अपनी पहचान बनाएं। अपने विभाग और खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। लोरमी में हो रहे कार्यों का दूसरे विकासखण्ड और तहसील अनुसरण करें, ऐसा काम करें।

श्री साव ने बैठक में लोरमी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति सहित सभी विभागों के कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने लोरमी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहर में नगर पालिका के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने को कहा। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए क्षेत्र में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री साव ने जिला खाद्य अधिकारी को अचानकमार क्षेत्र में बारिश के दिनों में पर्याप्त राशन का भंडारण करने को कहा। उन्होंने पीडीएस दुकानों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सभी दुकानों की व्यवस्था जांचने के भी निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने श्रम विभाग के अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निर्देशित किया। उन्होंने संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और योजनाओं की जानकारी देने शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने इन शिविरों में श्रमिकों को अन्य विभागों की योजनाओं की भी जानकारी देने को कहा। श्री साव ने जनपद पंचायत कार्यालय में हेल्प-डेस्क स्थापित कर लोगों को अपेक्षित जानकारियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुंगेली जिला पंचायत के सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, एसडीएम श्री जी.एल. यादव, तहसीलदार श्री शेखर पटेल, एसडीओपी सुश्री माधुरी धिरही, जनपद पंचायत के सीईओ श्री चंद्रकुमार धृतलहरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री लालजी चन्द्राकर, बीएमओ डॉ. जी.एस. दाऊ और बीईओ श्री डी.एस. राजपूत सहित सभी विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

रायपुर में दिव्य कला मेला, देश के चुनिंदा व्यंजनों का लें आनंद

रायपुर। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने 17 अगस्त को सुबह 11 बजे रायपुर के बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में दिव्य कला मेला की शुरुआत की। इस दौरान राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद रहे। सभी ने मेले के स्टॉलों अवलोकन किया।

इस मेले में देशभर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया गया है। मेले में लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों के पसंदीदा व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। यह मेला दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। यह मेला 16 अगस्त से 22 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह मेला देशभर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम लोगों के लिए एक रोमांचक अनुभव प्रस्तुत करेगा।

इस मेले में जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पादों हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई का काम और पैकेज्ड फूड आदि सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद एक साथ देख सकते हैं। रायपुर में यह 7 दिवसीय ''दिव्य कला मेला'' सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इसमें दिव्यांग कलाकारों और जाने-माने पेशेवरों की ओर से प्रस्तुतियाँ देने के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों की एक श्रृंखला भी देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम में लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों के अपने पसंदीदा व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। इस मेले का समापन दिव्य कला शक्ति नामक भव्य कार्यक्रम के साथ होगा, जिसमें देश के चुनिंदा दिव्यांग कलाकार अपनी कला, नृत्य तथा गायन का प्रदर्शन करेंगे।

दिव्य कला मेला दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) के उत्पादों और कौशल के विपणन और प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच दिया गया है। दिव्य कला मेला, रायपुर, छत्तीसगढ़ वर्ष 2022 से शुरू होने वाली श्रृंखला का 17वां मेला है। लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से गृह सज्जा और जीवन शैली, कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, पैकेज्ड फूड और ऑर्गेनिक उत्पाद, खिलौने और उपहार, व्यक्तिगत सहायक उपकरण, आभूषण, क्लच वेग आदि उत्पाद प्रदर्शित किये गये हैं।

फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से मिल रही ज्ञानवर्धक जानकारी

रायपुर। राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आजादी की 78 वीं वर्षगांठ पर छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का अवलोकन आम नागरिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों और स्कूली बच्चे उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। रायपुर के बी.पी. पुजारी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, पी.जी.उमाठे स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल रायपुर एवं अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए क्विज प्रतियोगिता भी रखी गई थी। जिसमें लगभग 100 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों को प्रदर्शनी के माध्यम से ज्ञानवर्धक बातें भी बताई जा रही है। ताकि बच्चों को आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो सके। क्विज के माध्यम से इतिहास, संस्कृति, अंग्रेजी, कृषि और रायपुर के प्रसिद्ध जगह और अन्य महत्वपूर्ण विषय के संबंध में प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे गए और सही जवाब देने वाले बच्चों को तुरंत इनाम देकर पुरस्कृत भी किया गया।

छाया चित्र का अवलोकन कक्षा 12वीं की प्रिया मसीह, शेख सानिया, नोसिन, यश साहू, सेजल चंद्राकर, राखी साहू, लक्ष्मी साहू, प्रतिभा, यश साहू, जतिन आदि छात्र एवं छात्राओं ने बताया की आज उनको प्रदर्शनी देखर बहुत अच्छा लगा। जिसमें भारत के छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिचय सहित फोटो प्रदर्शनी देखकर छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी मिली। विद्यार्थियों ने बताया कि छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी मिल रही है। अन्य साथियों को भी इसकी जानकारी देंगे ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। कक्षा 12वीं की शेख सानिया, राखी साहू, लक्ष्मी साहू एवं यश साहू, जतिन एवं अन्य विद्यार्थियों ने क्विज प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर भाग लिया।

1200 से अधिक शहीद जवानों के बनाए जाएंगे स्मारक

डिप्टी सीएम शर्मा का बड़ा ऐलान, शहीद के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी और स्कूल प्रवेश में आरक्षण

रायपुर। प्रदेश में भाजपा सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चला रही है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस से डिप्टी सीएम शर्मा बस्तर दौरे पर थे। बस्तर से वापसी के बाद उन्होंने आज अपने निवास में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में शहीद हुए जवानों को लेकर बड़ी घोषणा की और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि बस्तर और प्रदेश के अन्य स्थानों में शहीद हुए जवानों के स्मारक बनाए जाएंगे। एक साल में 1200 से अधिक जवानों के पाँच फीट के स्मारक बनाए जाएंगे, जिसमें शाहिदों के सभी डीटेल्स लिखे होंगे। उन्होंने बताया कि शहीद जवानों के परिवारों से सरकारी नौकरी और स्कूलों में बच्चों के प्रवेश में आरक्षण की बात हुई है। इस विषय पर राज्य सरकार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हर महीने के दूसरे बुधवार को डूल ऑफिस में जाकर शहीदों के परिजन अपनी बात रख सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। इसे लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन पर उनसे सभी विषयों पर चर्चा होगी, लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय है। उन्होंने बताया कि बस्तर में आकाशवाणी केंद्र में 15 घंटों के कार्यक्रम में 55 प्रतिशत अब हलबी गोंडी समेत अन्य भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की थी जिसपर मुहर लग चुकी है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने बीजापुर दौरे की जानकारी साझा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त को बस्तर के दौरे पर था। बस्तर में अलग ही उत्साह देखने को मिला। आत्मसमर्पित नक्सली बहनों ने मुझे राखी बांधी। ड्रख्श से जख्मी घायलों व शहीदों के परिजनों से मुलाकात हुई। दूसरे दिन पूर्ववर्ती गांव का भी दौरा किया, आम लोगों से मुलाकात की।

उन्होने आगे कहा कि गांव के लोगों में विकास की ललक दिखी। सड़क और बिजली की मांग रखी गई। पालनार का भी दौरा किया, समस्या निवारण शिविर लगा है। डिप्टी सीएम शर्मा ने बताया कि पालनार में 7 दिनों से कैंप लगा है और विभिन्न कार्यक्रम भी हो रहे हैं।

डिप्टी सीएम शर्मा ने बताया कि धुर नक्सल क्षेत्रों में बस सेवाएं फिर से शुरू होंगी। पालनार और पूर्वर्ति जैसे गांव में नक्सलवाद का कोई नामोनिशान नहीं है। सभी विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ना चाहते हैं, शीघ्र ही बस्तर शांत होगा।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली पाँच साल की सरकार में संस्थाओं को इंस्टीट्यूशनली बर्बाद किया गया। बड़े विभाग संस्था की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। प्रशासनिक संस्थाओं की बड़ी चोट लगी है। पूर्ववर्ती सरकार का उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार का था।

वहीं प्रदेश में कांग्रेस के गौ सत्याग्रह को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदर्शन किया, यह अच्छी बात है। लेकिन गौ माता को आंदोलन के चलते परेशान किया गया। प्रदर्शन के लिए क्रूरता किया गया। उन्हें पीड़ित करके लाया गया, ये नहीं करना था।

डिप्टी सीएम शर्मा ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों को लुटवाया-पिटवाया गया और आज खुद ही रैली में निकल पड़े हैं।

रायपुर में नशे का जखीरा डिस्पोज, कोरिया में नशे का सौदागर अरेस्ट

रायपुर। रायपुर के सिलतरा में एक निजी पावर प्लांट में पुलिस ने मादक पदार्थों को डिस्पोज किया है। ये मादक पदार्थ रायपुर रेंज के थानों से जब्त किए गए थे जिनमें रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी,महासमुंद और गरियाबंद जिला शामिल है। मादक पदार्थ डिस्पोज की कार्रवाई के दौरान रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा, रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह, धमतरी के एसपी आंजनेय वैष्णव भी मौजूद थे।

रायपुर रेंज के आईजी और उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष अमरेश मिश्रा ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों को डिस्पोज करने की कार्रवाई हुई है। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आदेश पर पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने ये कार्रवाई की है।

मादक पदार्थों के डिस्पोज की कार्रवाई में रायपुर जिले के कुल 157 एनडीपीएस के मामले में 2146 किलोग्राम गांजा, 58 हजार 747 नशीले टेबलेट, सीरप इंजेक्शन, 48 किलोग्राम अफीम डोडा, 206 ग्राम चरस/कोकीन ब्राऊन सुगर, जिला बलौदा बाजार के कुल 24 मामलों में 1022 किलोग्राम गांजा और 960 नशीले टेबलेट, जिला महासमुंद के 121 मामलों में 9 हजार 740 किलोग्राम गांजा, जिला धमतरी के 36 मामलों में 411किलोग्राम गांजा और 2451 नशीला टेबलेट, जिला गरियाबंद 31 मामलों में 1014 किलोग्राम गांजा और 253 नशीले टेबलेट को डिस्पोज किया गया।

वहीं कोरिया जिला में हो रहे नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पटना थाना पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 60 हजार की अवैध नशीली दवाइयां जब्त की है। इस मामले में ग्राम छिंदिया निवासी रामनारायण को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से एक हजार इंजेक्शन और एक हजार एविल टैबलेट बरामद किया गया है। जिसका अनुमानित मूल्य 60 हजार है। लेकिन अवैध रुप से इन दवाइयों को 5 गुना अधिक कीमत में बेचा जाता था। पुलिस के मुताबिक अवैध नशीली दवाओं का कारोबार में और भी नाम सामने आ सकते हैं।

ड्रग इंस्पेक्टर अलोक मिंज ने कहा मुझे खबर मिली थी कि सिंधिया में कोई नशीली दवाई लेकर आ रहा है। पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की गई। आरोपी के पास से एक हजार एविल इंजेक्शन डॉल्फिन दवाइयां मिली हैं। इसकी कीमत लगभग 60000 है। लेकिन बाजार में इसे लगभग 5 लाख रुपए में बेचा जाता।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1. रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)

निविदा सूचना क्र. 7/ व.ले लि/2024-25 — रायपुर दिनांक 14/08/2024

मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 01. रायपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के दिनांक 01/08/2010 से प्रचलित एस.ओ.आर. तथा आज दिनांक तक जारी संशोधन दर पर निम्नलिखित निविदा आमंत्रित किया जाता हैं। विवरण निम्नानुसार हैं-

स.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि रू. मे
1	2	3	4
1	Repair and Maintenance work of Dy. No. 6 of MBC from RD 0 m. to 7200 m.	Rs. 18.53 Lakhs	Rs. 14000/-
2	Repair and Maintenance work of MBC from RD 16000 m. to 19000 m.	Rs. 19.44 Lakhs	Rs. 14700/-
3	Repair and Maintenance work of MBC from RD 19000 m. to 22000 m.	Rs. 19.41 Lakhs	Rs. 14700/-
4	Repair and Maintenance work of Dy. No. 2 of MBC from RD 0 m. to 17000 m.	Rs. 19.98 Lakhs	Rs. 15000/-

निविदा प्रपत्र का मूल्य - रु. 750/-
कार्य पूर्णता का समयावधि - 2 माह वर्षा ऋतु सहित
निविदा प्राप्ति हेतु सक्षम श्रेणी - 'द' श्रेणी एवं ऊपर
निविदा क्रय की अंतिम तिथि - दिनांक 23.08.2024 समय 5:30 शाम तक
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि - दिनांक 30.08.2024 समय 5:30 शाम तक
निविदा खोलने की तिथि - दिनांक 02.09.2024 समय 11:30 से

निविदा के अन्य शर्ते कार्यालयीन अवधि में कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 01. रायपुर के कार्यालय में दिनांक 23.08.2024 तक देखा जा सकता है।

जी-242501865/3

कार्यपालन अभियंता
जल प्रबंध संभाग क्र. 1 रायपुर (छ.ग.)

लाल किले से प्रधानमंत्री ने दिए गहरे संकेत

ऋतुपर्ण दवे

जश्न -ए-आजादी यानी देश के सबसे बड़े दिन पर सबसे बड़े मंच लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार कुछ बहुत बड़ी बातें कहीं। इतना तो जतला दिया कि भले ही वह सहयोगियों के समर्थन से सरकार के मुखिया हैं लेकिन इतने भी कमजोर नहीं जितना समझाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने न केवल अपने विरोधियों पर करारा वार किया बल्कि समर्थकों को बता दिया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। नरेन्द्र मोदी ने कम्युनल सिविल कोड की जगह सैकुलर सिविल कोड की जरूरत बता एक बारगी सबको चौंकाया। उन्होंने सरकार के दोनों खास सहयोगियों को भी हैरान किया होगा जो हमेशा धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर रहे। उनका कहना कि जो कानून देश को धर्म के आधार पर बांटते हैं और ऊंच-नीच का कारण बनते हैं उनका आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। समय की मांग है कि अब एक सैकुलर सिविल कोड हो। अब इस पर नया कुछ क्या होगा देखने लायक होगा। हालांकि अब तक भाजपा यूनीफॉर्म सिविल कोड की ही बात करती रही है। कुछ राज्यों ने तो आगे आकर समर्थन भी किया। सैकुलर सिविल कोड पर नई बहस तय है। इतना ही नहीं वन नेशन वन इलैक्शन की बात फिर दोहराई। हालांकि वर्ष 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। यह सिलसिला 1957 में 5 अप्रैल को केरल में टूटा जब देश के पहले गैर कांग्रेसी एलमकुलम मनक्कल शंकरन यानी ई.एम.एस. नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार को तत्कालीन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाकर न केवल हटा दिया बल्कि वहां दोबारा 1960 में विधानसभा चुनाव हुए। तभी से अलग-अलग कारणों से कई राज्यों की सरकारों को गिराने का सिलसिला भी शुरू हुआ और टूटता गया। वन नेशन वन इलैक्शन पर पहले भी कई तर्क-वितर्क हो चुके हैं। ढेरों विविधताओं से भरे इस देश में कैसे एक साथ सारे चुनाव संभव होंगे, देखने लायक होगा। इससे इलैक्शन के खर्चों में कमी जरूर आएगी और आचार संहिता के चलते विकास कार्यों में रोक भी नहीं लगेगी। सभी राज्यों की विधानसभा भंग कर एक साथ चुनाव कराने की बात कैसे बनेगी? फिलहाल यह एक मॉडल के रूप में जरूर लुभाता है लेकिन व्यावहारिक कितना होगा नहीं पता। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने न्यायिक सुधार की बातें भी बड़ी बेबाकी से रखीं वह भी तब जबकि उनके ठीक सामने मेहमानों की कतार में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बैठे थे। सबको याद है कि 2014 में बहुमत में आते ही मोदी सरकार द्वारा संसद से पारित नैशनल ज्यूडिशियल अप्वाइंटमैंट्स कमीशन एक्ट यानी एन.जे.ए.सी. को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया और कहा कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम से होगी। 1993 में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर नई व्यवस्था देकर सर्वोच्च न्यायालय ने कलैक्टिव विजडम के तहत कॉलेजियम प्रणाली बनाई थी। 'एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ' मामले में आए ऐतिहासिक फैसले से भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक नई दिशा मिली। इससे पहले, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका प्रमुख होती थी जिसमें राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। कॉलेजियम सिस्टम में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीश सामूहिक रूप से हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और प्रोमोशन का निर्णय लेते हैं। मोदी ने एक और बड़ी बात कही जिसमें एक लाख ऐसे नौजवानों को देश भर में जनप्रतिनिधि के रूप में आगे लाने की है, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं हो। अब पक्ष-विपक्ष इसके क्या मायने निकालेगा इसका इंतजार है। लेकिन जिस बेबाकी से बातें कीं उसके परिणाम दूरगामी जरूर होंगे। सरकार के खास सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पुत्र नारा लोकेश खुद अपने पिता के मंत्रिमण्डल में तीसरे क्रम पर शपथ लेने वाले मंत्री हैं। वहीं भाजपा और कई उसके समर्थक तमाम जनप्रतिनिधि पारिवारिक पृष्ठ भूमि के चलते बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। महिला अपराधों पर भी प्रधानमंत्री की जायज चिंता सामने आई। बलात्कार की घटनाओं का मीडिया में छाए रहना लेकिन ऐसे अपराधियों को मिली सजा पर समाचार न बनने पर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए इसे भी उतना ही स्थान देने की वकालत की। महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ रहा है लेकिन लगातार अत्याचार होना चिंताजनक है। 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से 100 मिनट के अब तक के सबसे लंबे भाषण में प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के दीमक पर पीड़ा झलकी। भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी जंग को दोहराना बड़ा इशारा है।

अखंड भारत होगा साकार

प्रह्लाद सबनानी

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त 2024 को पूरे भारतवर्ष में 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूम धाम से मनाया गया। दरअसल, भारतीय नागरिक 15 अगस्त 1947 के पूर्व अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत पराधीन थे एवं 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से मुक्त होकर भारतीय नागरिक स्वाधीन हुए। इसलिए इस पर्व को स्वाधीनता दिवस कहना अधिक तर्कसंगत होगा। स्वतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलाकर बना है (1) स्व; एवं (2) तंत्र। अर्थात स्वयं का तंत्र, इसलिए स्वतंत्रता दिवस कहना तो तभी न्यायोचित होगा जब स्वयं का तंत्र स्थापित हो। भारत के नागरिकों में आज स्व के भाव के प्रति जागृति तो दिखाई देने लगी है और वे भारत के हित सर्वोपरि हैं की चर्चा करने लगे हैं। परंतु, भारत में तंत्र अभी भी मां भारती के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कभी कभी असामाजिक तत्व अपने भारत विरोधी एजेंडा पर कार्य करते हुए दिखाई दे जाते हैं और भारत के विभिन्न समाजों में अशांति फैलाने में सफल हो जाते हैं। स्व के तंत्र के स्थापित होने से आश्य यह है कि देश में हिंदू सनातन संस्कृति का अनुपालन सुनिश्चित हो।

प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित लगभग समस्त क्षेत्रों में भारतीय सनातन संस्कृति का दबदबा था। भारत को उस खंडकाल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से पूरे विश्व से विद्यार्थी भारत में आते थे। भारत पर शक, हूण, कुषाण एवं यवन के आक्रमण हुए, परंतु भारत पर उनके कुछ समय के शासन के पश्चात वे भारतीय सनातन संस्कृति में ही रच बस गए एवं भारत का हिस्सा बन गए। परंतु, अरब के देशों से मुसलमान एवं ब्रिटेन से अंग्रेजों के भारत पर चले शासन के दौरान उन्होंने भारतीय नागरिकों का बलात धर्म परिवर्तन करवाया, स्थानीय नागरिकों पर अकल्पनीय अत्याचार किए। भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों, मंदिरों एवं ज्ञान के स्थानों को नष्ट किया। अंग्रेजों ने तो भारतीय नागरिकों के साथ छल कपट करते हुए यह भ्रम फैलाया कि अंग्रेजों ने ही भारतीय नागरिकों को जीना सिखाया है अन्यथा भारतीय समाज तो असभ्य, अनपढ़ गंवार था। उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति पर गहरी चोट की। वे भारतीयों में हीन भावना भरने में सफल रहे। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को नष्ट किया। गुरुकुल नष्ट किए। अंग्रेजों को नौकर चाहिए थे अत: तात्कालिक शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए। इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली देश में आज भी चल रही है, जिसके अंतर्गत शिक्षित भारतीय केवल नौकरी करने के लिए ही उतावाले नजर आते हैं। वे अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के प्रति रुचि ही प्रकट नहीं करते हैं। भारत में उद्योगपति अपने परिवार की विरासत से ही निकले हैं।

भारत को आक्रांताओं एवं अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से समय समय पर भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों ने युद्ध भी लड़े एवं अपने स्तर पर उस खंडकाल में सफलता भी अर्जित की। जैसे, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा आदि के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार, अंगेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले वीर क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के नाम सहज रूप से लिए जा सकते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मशाल आगे लेकर चलने वाले कई योद्धाओं में महात्मा गांधी, सरदार पटेल एवं सुभाषचंद्र बोस भी शामिल रहे हैं। इसी समय में विवेकानंद एवं डॉक्टर हेडगेवार ने भी सांस्कृतिक चिंतक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन सफलतापूर्वक किया था। इस प्रकार, अंतत: भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली एवं भारतीय नागरिकों को स्वाधीनता प्राप्त हुई। भारत के लिए यह एक नई सुबह तो थी परंतु यह साथ में विभाजन की त्रासदी भी लेकर आई थी। पूर्व एवं पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में एक नए देश ने भी जन्म लिया और इस दौरान करोड़ों नागरिकों ने अपनी जान गवाईं थी।

आखिर भारत का विभाजन हुआ क्यों? यदि इस विषय पर विचार किया जाय तो ध्यान में आता है कि दरअसल अंग्रेजों ने यह भ्रम फैलाया कि भारत में आर्य बाहर से आए हैं और इस प्रकार वे भारतीय नागरिकों में मतभेद पैदा करने में सफल हुए। साथ ही, उन्हें भारतीय नागरिकों में यह भाव पैदा करने में भी सफलता मिली कि भारत एक भौगोलिक इकाई है एवं यह कई राज्यों को मिलाकर एक देश बना है जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई होती है न कि भौगोलिक इकाई। उस खंडकाल विशेष में अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया मुस्लिम तुष्टिकरण भी भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रवादी मुसलमानों की उपेक्षा की गई थी एवं उस समय की जनभावना को बिलकुल ही नकार दिया गया था, इसके उदाहरण के रूप में 'वन्दे मातरम' कहने पर अंकुश लगाना एवं राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा ध्वज को स्वीकार नहीं करना, का वर्णन किया जा सकता है। और फिर, उस समय विशेष पर भारत का नेतृत्व भी मजबूत हाथों में नहीं था। उक्त कई कारणों के चलते भारत को विभाजन की विभीषिका को झेलना पड़ा था और करोड़ों नागरिक इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे।

वैसे तो भारत को पूर्व में भी खंडित किया जाता रहा है परंतु वर्ष 1947 में हुआ विभाजन सबसे अधिक वीभत्स रहा है। वर्ष 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था, वर्ष 1914 में तिब्बत को भारत से अलग कर दिया गया था, वर्ष 1906 में भूटान एवं वर्ष 1904 में नेपाल को भारत से अलग कर दो नए देश बना दिये गए थे एवं वर्ष 1876 में अफगानिस्तान ने नए देश के रूप में जन्म लिया था। यह सभी विभाजन भारत को पावन भूमि को विखंडित करते हुए सम्पन्न हुए थे। यह सिलसिला वर्ष 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी रुका नहीं एवं वर्ष 1948 में भारत के भूभाग को विखंडित कर श्रीलंका के रूप में नए देश का जन्म हुआ। वर्ष 1948 में ही पाकिस्तान के कुछ कबीलों ने भारत के कश्मीर क्षेत्र पर आक्रमण कर कश्मीर के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे आज 'पाक आकुपाईड कश्मीर' कहा जाता है। वर्ष 1962 में आक्साई चिन भी भारत से विखंडित हो गया था।

उक्त विखंडित हुए भूभाग से भारत का नाता आज भी बना हुआ है। जैसे, अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित रही हैं, जिन्हें बाद के खंडकाल में तालिबान ने खंडित कर दिया है। महाभारत काल में गांधारी आज के अफगानिस्तान राज्य की निवासी रही है। अफगानिस्तान शिव उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसी प्रकार पाकिस्तान में तो तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा है, जिसमें विश्व के अन्य देशों से विद्यार्थी अधय्यन के लिए आते थे। हिंगलाज माता का मंदिर है, भगवान झूलेलाल का अवतरण इस धरा पर हुआ था, साधु बेला, संत कंवरराम, ऋषि पिंगल, ऋषि पाणिनि भी इसी धरा पर रहे हैं। भगत सिंह, लाला लाजपत राय एवं आचार्य कृपलानी जैसे देशभक्तों ने भी इसी धरा पर जन्म लिया था। बंगला देश में भी आज ढाकेश्वरी मंदिर स्थित है जिसके नाम पर ही बांग्लादेश की राजधानी को ढाका कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस एवं विपिन चंद्र पाल जैसे महान देशभक्तों ने भी इसी धरा पर जन्म लिया है। नेपाल तो अभी हाल ही के समय तक हिंदू राष्ट्र ही रहा है एवं यहां पर कैलाश मानसरोवर, पशुपति नाथ मंदिर, जनकपुर जहां माता सीता का जन्म हुआ था एवं विश्व प्रसिद्ध लुम्बिनी, आदि नेपाल में ही स्थित हैं। इस दृष्टि से यह ध्यान में आता है कि भारत को एक बार पुन: अखंड क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि भारत से अलग हुए इन सभी देशों की सांस्कृतिक विरासत तो एक ही दिखाई देती हैं।

महर्षि अरविंद तो कहते ही थे कि भारत अखंड होगा क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है। स्वामी विवेकानंद जी को भरोसा था कि भारत एक सनातन राष्ट्र के रूप में अखंड होगा ही। आज हम सभी भारतवासियों को यह विश्वास अपने मन में जगाना होगा कि भारत एक अखंड राष्ट्र होगा ही इसके लिए मेहनत की पराकाष्ठा जरूर करनी होगी। हिंदू एक संस्कृति है न कि पूजा पद्धति, इस प्रकार का व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अखंड भारत में समस्त मत पंथों को मानने वाले नागरिकों को अपनी पूजा पद्धति के लिए छूट होगी ही। इस संदर्भ में विघटनकारी सोच की राजनैतिक पराजय अति आवश्यक है। भविष्य में केवल भारत ही अखंड होगा, ऐसा भी नहीं है। इसके पूर्व एवं पश्चिमी जर्मनी एक हो चुके हैं, वियतमान में भी इसी संदर्भ में बाहरी षड्यंत्र विफल हो चुके हैं। इजराईल देश भी तो अनवरत साधना से ही बन पाया है, फिर भारत क्यों नहीं अखंड हो सकता।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

लक्षण-समन्वय-विवेचन (भाग-3)

गतांक से आगे...

मुद्रित और विभिन्न पुस्तकालयों में सुरक्षित सब मिल कर भी जहाँ तक आजकल पता चलता है, उपयुक्त संख्या का दशाँश अवशिष्ट नहीं है! कहां है वह धनुर्वेद जिसके अध्ययन से द्रोण, अर्जुन और कर्ण जैसे वीरों ने शब्दवेध चललक्ष्य-वेध तथा वर्तुलवेध आदि लोकोत्तर कर्तब कर दिखाये थे । आत्मा और परमात्मा की तार को मिला देने वाला गन्धर्ववेद किस गुफा में अनन्त समाधि लगाए बैठा है? समुद्रों के पुल बांध कर जगत् को अद्यावधि चकित करने वाला, और सहस्त्रों सेना सहित भगवान् राम को अकिंचित् काल में अयोध्या पहुँचाने वाला शिल्प जिस स्थापत्यवेद का विषय था ? आज वह भी हम से ओझल हो रहा है ?

न्यून-अधिक-पाठ- पाठों की न्यूनता और अधिकता, तथा अन्यान्य वैषम्य जैसे पुराणों में उपलब्ध होते हैं वैसे ही वेदों की विभिन्न शाखाओं में पाए जाते हैं । वास्तव में शाखाभेद का प्रधान कारण ही पठान्तर-प्रणाली है। इस विषय में हम स्वयं कुछ अधिक न कहते हुने वैदिक-साहित्य के विशेषज्ञ श्री सत्यव्रत सामाश्रमी के विचार उद्धृत करना पर्याप्त समझते हैं। आप लिखते हैं कि:- संहिताओं के अति प्राचीन होने से उनमें काल-देश व्यक्ति के विभिन्न होने के कारण, पढ़ते समय उच्चारण और पाठ में भेद हो गया। इसी प्रकार पाठ की न्यूनता और अधिकता भी हो गई।

यह एक स्वाभाविक परिवर्तन है जो हजार प्रयत्न करने पर भी टल नहीं सकता। वेदों की रक्षा के लिए उनके एक एक अक्षर को गिन लिया गया तो भी पाठान्तर का प्रवाह रुक न सका, तब तो मन्त्रार्थों का यथार्थक्रम स्थिर रखने के लिये ऋषि व्यग्र हो उठे और उन्होंने पद क्रम घन जटा माला शिखा लेखा ध्वज दण्ड और रथ आदि पद्धतियों द्वारा मन्त्राक्षरों के पौर्वापर्य को यथातथा स्थिर रखा। **क्रमश: ...**

अजेय योद्धा थे बाजीराव पेशवा प्रथम

दीपक कुमार त्यागी

पेशवा बाजीराव बल्लाल का जन्म 18 अगस्त सन् 1700 को चित्ताबन कुल के ब्राह्मण परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी मराठा छत्रपति शाहूजी महाराज के प्रथम पेशवा (प्रधानमंत्री) थे। बाजीराव का एक छोटा भाई भी था चिमाजी अप्पा। बाजीराव अल्पायु से ही अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभियानों में जाया करते थे।

हर-हर महादेव के युद्धघोष के साथ देश में अटक से लेकर कटक तक केसरिया ध्वज लहरा कर हिन्दू स्वराज लाने का जो सपना वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसको काफी हद तक मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा या प्रधानमंत्री वीर बाजीराव प्रथम ने पूरा किया था। जिस वीर महायोद्धा बाजीराव पेशवा प्रथम के नाम से अंग्रेज शासक थर-थर कांपते थे, मुगल शासक बाजीराव से इतना डरते थे कि उनसे मिलने तक से भी घबराते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम ही अकेले ऐसे महावीर महायोद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा, साथ ही वीर महाराणा प्रताप और वीर छत्रपति शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा प्रथम का ही नाम आता है जिन्होंने मुगलों से बहुत लंबे समय तक लगातार लोहा लिया था। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट एक ऐसे महान योद्धा थे। जिन्होंने निजाम, मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक को युद्ध के मैदान में कई-कई बार करारी शिकस्त दी थी, बाजीराव पेशवा के समय

में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80 प्रतिशत भारत पर उनका शासन था। ऐसा रिकॉर्ड वीर छत्रपति शिवाजी तक के नाम पर भी नहीं है। वह जब तक जीवित रहे हमेशा अजेय रहे, उनको कभी भी कोई हरा नहीं पाया।

हालांकि इस महावीर अजेय योद्धा के साथ हमारे देश के इतिहासकारों ने कभी न्याय नहीं किया, उन्होंने एक महान योद्धा को हमेशा गुमनाम नायक बनकर ही रहने दिया, बाजीराव को इतिहास ने उनका तय सम्मान कभी नहीं दिया, देश में फिल्म बाजीराव मस्तानी आने तक तो उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, अधिकांश लोगों ने उसके बाद ही इस महान योद्धा के बारे में जाना और समझा।

बाजीराव पेशवा को लोग बाजीराव बल्लाल भट्ट और थोरले बाजीराव के नाम से भी जानते थे। छत्रपति शिवाजी के बाद वह गुरिल्ला युद्ध तकनीक के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, व्यूह रचना एवं कारगर रणकौशल के बलबूते पर मराठा साम्राज्य का देश में बहुत तेजी से सबसे अधिक विस्तार किया था।

बाजीराव के समय में भारत की जनता मुगलों के साथ-साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। यह आक्रांता भारत के देवस्थान मंदिरों को तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करते, महिलाओं व बच्चों को मारते व उनका भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। उनकी वीरता को देखकर लोग उन्हें शिवाजी का साक्षात अवतार मानने लगे थे।

रूस में यूक्रेनी घुसपैठ में अमेरिका निर्मित हथियार

अंकित सिंह

रूस-यूक्रेन युद्ध के तीसरे वर्ष में युद्ध मैदान के हालात में आये बड़े परिवर्तन ने सबको चौंका दिया है। जिस तरह यूक्रेन रूस को उसके घर में घुसकर मार रहा है उससे समूची दुनिया हैरान रह गयी है। हालांकि यहां एक सवाल यह उठ रहा है कि यूक्रेन अमेरिकी हथियारों के साथ जिस तरह रूस में हमले कर रहा है क्या उससे अमेरिका की हथियार नीति का उल्लंघन नहीं हो रहा है? हम आपको बता दें कि यूक्रेन ने कहा है कि उसके सैनिक 6 अगस्त को घुसपैठ शुरू करने के बाद से अब तक रूस में 35 किमी (21 मील) तक घुस आए हैं। कीव का कहना है कि उसे रूसी भूमि पर कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को रूस से बचाने के लिए एक बफर जोन बना रहा है।

दूसरी ओर, अमेरिका का कहना है कि अगर यूक्रेन अमेरिकी हथियारों और वाहनों का उपयोग करके गांवों और अन्य गैर-सैन्य ठिकानों पर कब्जा करना शुरू कर देता है, तो इससे अमेरिकी हथियार नीति पर सवाल उठ सकते हैं। अमेरिका को यह भी चिंता है कि युद्ध में अमेरिका और नाटो देशों के हथियारों का रूस के खिलाफ खुलकर विरोध होने से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़क सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि वाशिंगटन की हथियार नीति यूक्रेन द्वारा रूस पर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाई गई थी। अमेरिका का कहना है कि राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने हमले के समर्थन या विरोध में कोई मजबूत सार्वजनिक रुख नहीं अपनाया है।

वैसे अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रूस में यूक्रेनी घुसपैठ में कौन से अमेरिका निर्मित हथियार या उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। हम आपको बता दें कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने के बाद से अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और उसे 50 बिलियन डॉलर से अधिक के सैन्य उपकरण प्रदान किए हैं। हालांकि अपने भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रूस के साथ व्यापक संघर्ष से बचने की कोशिश करते हुए, बाइडन प्रशासन ने शुरू में अपने हथियारों के उपयोग पर सख्त शर्तें लगा दीं थीं। लेकिन अब उन शर्तों को धीरे-धीरे ढीला कर दिया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदमीर ज़ेलेंस्की की अपील के बावजूद अमेरिका अभी भी रूसी क्षेत्र पर लंबी दूरी के हमलों के लिए अपने हथियारों के उपयोग की अनुमति नहीं दे रहा है। वैसे बाइडन प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से लंबी दूरी को परिभाषित नहीं किया है। विशेषज्ञों का

इस बारे में कहना है कि अमेरिका ने धीरे-धीरे यूक्रेन द्वारा अपने हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंधों में ढील दे दी है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप या अमेरिका के खिलाफ आशंका के मुताबिक अब तक कोई हमला नहीं किया है।

हम आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने हाल ही में कहा था कि हम बहुत स्पष्ट और सुसंगत रहे हैं कि हम वास्तव में यूक्रेन को अपनी सीमाओं के अंदर आक्रामकता के खिलाफ खुद का बचाव करने पर ध्यान केंद्रित करते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन के बाहर हमलों को न तो प्रोत्साहित करते हैं और न ही इसकी अनुमति देते हैं, सिवाय उन आपातकालीन परिस्थितियों के, जहां हमारा मानना है कि सीमा पर वे कुछ आसन्न खतरों का सामना कर रहे हैं।

हम आपको बता दें कि यूक्रेन ने सीमा पार से बिजली की तेजी से रूस पर हमला किया था। अब यूक्रेनी सैनिक बड़े जोखिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और रूस को वापस अपने पैर जमाने से रोकना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने पिछले हफ्ते पश्चिमी रूसी क्षेत्र कुर्स्क में हजारों सैनिकों को तैनात किया। यूक्रेन ने अपने सैनिकों द्वारा जब्त किए गए शहरों में रूसी झंडे उतार दिए और पहली बार युद्ध में मास्को पर बढ़त बना ली। इस बारे में कीव में अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन अपने उत्तर को रूसी हमलों से बचाने के लिए जब्त किए गए रूसी क्षेत्र को बफर ज़ोन के रूप में उपयोग करेगा। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के प्रमुख ऑलेक्ज़ेंडर सिर्स्की ने कहा है कि कीव ने कुर्स्क के कब्जे वाले हिस्से में एक सैन्य कमांडेंट का कार्यालय स्थापित किया है। सिर्स्की ने कहा है कि कब्ज़ा किया गया क्षेत्र 1,150 वर्ग किमी से अधिक है। इस बीच, पूर्व यूक्रेनी रक्षा मंत्री एंड्री ज़ागोरोड्न्युक ने एक साक्षात्कार में कहा है कि कुर्स्क में यूक्रेन का लक्ष्य यह भी है कि डोनबास के पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्र से रूसी सेना को भगाया जाये जहां उसने लगातार बढ़त हासिल की है।

इस बीच, रूस ने कहा है कि वह सीमा सुरक्षा बढ़ाएगा, कमान और नियंत्रण में सुधार करेगा और कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के बाद अतिरिक्त बल भेजेगा। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन द्वारा पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ भी चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपर राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा है कि कुर्स्क में, यूक्रेन में या कहीं और अमेरिकी हथियारों का उपयोग अगर होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह हमला बड़ा झटका तो है ही साथ ही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूस पर सबसे बड़ा आक्रमण है जिसने रूसी सेनाओं की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि रूसी क्षेत्र पर यूक्रेनी हमला एक आतंकवादी आक्रमण है क्योंकि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। पुतिन ने कहा कि रूस हमले का उचित जवाब देगा लेकिन पहला काम रूसी क्षेत्र से सभी यूक्रेनी सैनिकों को बाहर निकालना है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन शांति वार्ता में सौदेबाजी के लिए इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहता है।

बहरहाल, यह भी माना जा रहा है कि रूसी भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने से यूक्रेनी सेना को संभावित रूप से भारी नुकसान हो सकता है। ऐस इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र की जनता यूक्रेन को एक बड़े दुश्मन के रूप में देखती है।

आज का इतिहास

1926 मौसम मानचित्र पहली बार टेलीविजन पर प्रसारित किया गया।
1937 टोयोटा इंडस्ट्रीज की सफलता के बाद टोयोटा इंडस्ट्रीज के मूल संस्थापक साकी टोयोदा के बेटे कीइचिरो टोयोदा ने जापान में टोयोटा मोटर कंपनी की स्थापना की।
1945 ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे पर सुभाषचन्द्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मौत हुई।
1948 ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 की एशेज श्रृंखला जीत पूरी की, जिससे उन्हें एक मैच गंवाए बिना इंग्लैंड का पूरा दौरा खेलने वाला पहला टेस्ट क्रिकेट मैच होने के लिए द इनविजनल का तत्कालीन नाम कमाया गया।
1958 व्लादिमीर नाबोकोव के विवादास्पद उपन्यास लोलिता को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित किया गया।
1963 जेम्स मेरेडिथ मिसिसिपी विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एक डिग्री खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी अमेरिकी है; वे विश्वविद्यालय के पहले अश्वेत छात्र भी थे।
1964 दक्षिणी अफ्रीका को ओलम्पिक खेलों में भाग लेने से रोक दिया गया। यह प्रतिबंध दक्षिणी अफ़्रीका की सरकार की नीतियों के चलते लगा था।
1966 वियतनाम वॉर-मेंबर्स ऑफ़ द 6 वीं बटालियन ऑफ़ द रयल ऑस्ट्रेलियन रेजीमेंट के सदस्यों ने लॉन्ग टैन की लड़ाई में विएट कांग यूनिट के साथ चारों तरफ से घेर लिया और उन पर हमला किया, लेकिन सुदृढीकरण आने तक उन्हें कई घंटों तक रोकना पड़ा।
1973 अमेरिका के बॉस्टन में पहले एफ एम रेडियों स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई।
1983 तूफान एलिसिया ने अमेरिका के टेक्सास में गैल्वेस्टन के पास भूस्खलन किया, जिससे 2.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और 21 लोग मारे गए।
1989 कोलम्बियाई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलन को सोचाचा, कुंडमारमस्का शहर में एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान हत्या कर दी गई थी।

भारत का संविधान : राज्य मनमानी नहीं कर सकते

सीबीपी श्रीवास्तव

भारत के राजनीतिक स्वरूप की विशिष्टता इसकी एकात्मक संघीय प्रकृति है, जिसे आचार्य दुर्गा दास बसु ने 'चरित्र में परिसंघीय और आत्मा में एकात्मक' के रूप में वर्णित किया है। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, 1977 मामले में ग्रैनविले ऑस्टिन का हवाला दिया है, जिन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान शायद पहला ऐसा संविधान है, जिसने शुरू से ही एएच बर्च द्वारा संकल्पित सहकारी संघवाद की संकल्पना को अपनाया है। यानी संघ और राज्य तथा राज्य और राज्य परस्पर सहयोग और समन्वय से कार्य करेंगे, ताकि संविधान द्वारा निर्धारित कल्याण के साझा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। न्यायालय ने माना है कि संविधान ने एक ऐसी केंद्र सरकार की संकल्पना की है, जो इस अर्थ में 'उभयचर' है कि वह परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार संघीय या एकात्मक तल पर कार्य कर सकती है।

एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 मामले में शीर्ष न्यायालय ने भारत के संघवाद को 'व्यावहारिक संघवाद' कहा है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण तो हुआ है, पर इसका झुकाव संघ की ओर है। हरियाणा बनाम पंजाब राज्य, 2004 मामले में 'अर्ध-संघीय' शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1974 मामले में न्यायालय ने इसे 'परिसंघीय से अधिक एकात्मक' कहा था। शीर्ष न्यायालय के इन विचारों से स्पष्ट होता है कि भारत की राजनीतिक संरचना को विषम परिसंघ कहा जाना सही है, जहां विधायी शक्तियों का वितरण दो अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाली स्वायत्त सरकारों की जरूरतों के अनुसार किया गया है, हालांकि दोनों में से किसी को भी कमजोर या मजबूत नहीं बनाया गया है। इसे ही हम शक्तियों का न्यायसंगत वितरण कहते हैं।

हाल ही में, भारत के प्रधान न्यायाधीश ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2024 मामले में कहा कि, भारतीय परिसंघ को विषम परिसंघ के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि इसका झुकाव केंद्र की ओर है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत केंद्र सरकार का गठन है। पर राज्यों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर कानून बनाने की संप्रभु शक्तियां दी गई हैं। परिसंघीय ढांचे में प्रत्येक इकाई को एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता के साथ अपने मूल

सांविधानिक कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए। संविधान की व्याख्या इस तरह होनी चाहिए कि परिसंघीय चरित्र कमजोर न हो। न्यायालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य विधानसभाएं अपने आरक्षित क्षेत्रों में संघ के अधीन न हों।

संविधान के अनुच्छेद एक के तहत, भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में स्थापित किया गया है, जहां राज्यों के निर्माण का अधिकार संघ का है और राज्य भारत के आवश्यक भाग हैं। अनुच्छेद 245 कानून बनाने के लिए भारत के राज्यक्षेत्र का वर्गीकरण करता है और संघ व राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रयोज्यता की सीमा का प्रावधान करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने के लिए विषयों का बंटवारा करता है, फिर भी संसद को अवशिष्ट शक्तियों के तहत उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है और जो नए उभरने वाले विषय हैं। यही परिसंघीय ढांचे को विषम परिसंघ बनाता है।

इसी प्रकार, वित्तीय शक्तियां भी संघ में निहित हैं, जिसके लिए अनुच्छेद 109 का खंड (1) उल्लेखनीय है, जो यह प्रावधान करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। विषम परिसंघ के ये प्रावधान भारत को एक कार्यात्मक परिसंघ भी बनाते हैं, जिसमें वित्तीय और नए उभरने वाले विषयों की शक्तियां राज्यों में निहित नहीं होती हैं।

सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, हालांकि, संघ सूची के कुछ विषयों को राज्य के विषयों पर वरीयता दी गई है, फिर भी यह परिसंघ को कमजोर नहीं बनाता है। जैसे, राज्य सूची की प्रविष्टि 17 में पानी यानी जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति सूची ढ्ढ की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन हैं।

2024 के मिनरल एरिया डेवलपमेंट मामले में दिए गए फैसले में उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से कर लगाने संबंधी राज्यों की विधायी क्षमता की जांच की। मुख्य प्रश्न यह जांचना था कि क्या खनन पट्टों पर रॉयल्टी को कर माना जाना चाहिए और क्या संसदीय कानून, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के बाद राज्यों को खनिज अधिकारों पर रॉयल्टी/कर लगाने का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्य विधानसभाओं में निहित है। संसद के पास सूची-1 की प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है, यह एक सामान्य प्रविष्टि है। चूंकि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति सूची-2 की प्रविष्टि 50 में उल्लिखित है, इसलिए संसद उस विषय वस्तु के संबंध में अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है। राज्यों की विधायी क्षमता पर केवल इसलिए सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि भारतीय परिसंघ विषम है।

संविधान निर्माताओं ने संघ और राज्यों के बीच किसी भी संभावित टकराव को रोकने के लिए सातवीं अनुसूची में विषयों को बहुत स्पष्टता से सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा, समन्वय का सिद्धांत समवर्ती सूची में अच्छी तरह से स्थापित है, जिसमें संघ और राज्य, दोनों कानून बना सकते हैं। भारत के संविधान ने संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है, जो दोनों में से किसी को भी संप्रभु होने से रोकता है। इस अर्थ में, संघ और राज्यों, दोनों की विधायी क्षमता इतनी संतुलित है कि परिसंघीय विषमता कानून बनाने के कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है, ताकि संसाधनों को न्यायसंगत ढंग से वितरित करके व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का साझा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए लोकतांत्रिक शासन को सर्व-समावेशी और सर्वव्यापी बनाया जा सके।

बंगला देश पर प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख के मिलते जुलते विचार

कृष्णमोहन झा

भारत के 78 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक लालकिले से राष्ट्र के नाम अपने संदेश में बंगला देश के घटना क्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए वहां जल्द हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई है । प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी वहां हिन्दू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। भारत चाहता है कि पड़ोसी देश सुख और शांति के रास्ते पर चले। प्रधानमंत्री ने शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि यही हमारे संस्कार हैं। आने वाले समय में बंगला देश की विकास यात्रा में भारत सहभागी बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगला देश की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को लेकर जो चिंता व्यक्त की उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी साझा किया है। सरसंघचालक ने नागपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के पश्चात् अपने संबोधन में बंगला देश का नाम लिए बिना कहा कि भारत के पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे हैं और वहां रहने वाले हिन्दू अल्पसंख्यकों को बिना कारण ही उसकी तपिश झेलना पड़ रही है। भारतवर्ष का दायित्व स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता तो है लेकिन यह हमारी परंपरा है कि भारत अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। हमने किसी पर हमला नहीं किया बल्कि जब जो संकट में था उसकी मदद की । संघ प्रमुख ने सरकार से बंगला देश में संकटग्रस्त हिन्दुओं की मदद करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि सरकार निश्चित रूप से ऐसा करेगी परंतु इसके लिए सभी लोगों को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इसी आशय के विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने हिंसाग्रस्त बंगला देश में हिन्दुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा की जरूरत पर बल देते हुए कहा था कि बंगला देश की अंतरिम सरकार को वहां जारी उपद्रवों को रोकने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। सरकार्यवाह ने विश्व समुदाय और भारत के राजनीतिक दलो से बंगला देश में हिंसा का शिकार बने हिंदू, बौद्ध आदि अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि बंगला देश में हाल के हिंसक उपद्रवों में हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। इस्कॉन मंदिर को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बंगला देश की स्थिति पर संसद में अपने बयान में कहा था कि भारत सरकार वहां हिन्दू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर निगरानी रख रही है। बंगला देश में करीब 19000 हिंदू अल्पसंख्यक हैं जिनमें से 9 हजार छात्र हैं । बंगला देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू होने के पहले करीब आधे हिंदू अल्पसंख्यक भारत लौट आए हैं। सरकार वहां रहे हिन्दू परिवारों के निरंतर संपर्क में है और संकट की इस घड़ी में उनके साथ है। बंगला देश का घटनाक्रम भारत के लिए नि:संदेह चिंताजनक है। भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्वाह करने वाली हसीना वाजेद सरकार का स्थान मोहम्मद युनूस की अंतरिम सरकार ने ले लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री और बंगला देश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है जिनकी सरकार का झुकाव हमेशा चीन और पाकिस्तान की ओर रहा जबकि बंगला देश की प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना वाजेद के कार्यकाल में बंगला देश और भारत के बीच प्रगाढ़ मैत्री संबंध बने रहे । अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार पद का कार्य भार संभालने के बाद मोहम्मद युनूस ने उपद्रवकारियों से यूं तो सख्त लहजे में कहा है कि वे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना तत्काल बंद करें परंतु उनकी सख्ती के जब तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आते तब तक यह सख्ती दिखावटी ही मानी जाएगी और ऐसी स्थिति में भारत को वहां हिंदुओं के जान-माल की सुरक्षा के लिए और प्रभावी कदमों पर विचार करने पर विवश होना पड़ेगा।

चुनाव में चेहरे से चमक लाने की कोशिश

अमिताभ श्रीवास्तव

इस बात में अब कोई शक नहीं है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी प्रवक्ता संजय राऊत एक ही पटकथा से तैयार संवाद बोलते हैं। यह बात और है कि राऊत रोज सुबह नौ बजे और उद्धव ठाकरे अवसर के अनुसार बोलते हैं। इस बात की पुष्टि शुक्रवार को आयोजित महाविकास आघाड़ी की रैली से हो जाती है, जहां शिवसेना प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए अपना चेहरा घोषित करें, वह समर्थन देने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन पहले राऊत ने भी यही कहा था कि उद्धव ठाकरे के मुकाबले यदि कांग्रेस और राकांपा (शरद पवार गुट) के पास उम्मीदवार है तो बताएं। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट अपने नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहता है और उसमें उन्हें राकांपा (शरद पवार गुट) के नेता शरद पवार की सहमति की आवश्यकता है।

यदि पवार का साथ मिलता है तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पर दबाव बनाया जा सकता है और कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर मतदाताओं के समक्ष यह साबित किया जा सकता है कि शिवसेना(उद्धव ठाकरे गुट) भले ही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हिस्सा है, मगर वह अपनी पहचान और सर्वोच्च स्थान दोनों रखता है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और नौ सीटें, कांग्रेस ने 17 पर चुनाव लड़कर 13 तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर आठ सीटें जीती थीं। कुल मिलाकर तीनों के खाते में तीस सीटें आईं। एक निर्दलीय का भी समर्थन मिला। इन परिणामों से दो बातें साफ हुईं। एक, गठबंधन में तीनों दलों को लाभ हुआ, दूसरी, यह भी स्पष्ट हुआ कि किसे अधिक किसे कम फायदा हुआ। कांग्रेस को लगा कि उसकी पुरानी ताकत वापस आई तो शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) को अपनी जमीन बचाने का भरोसा पैदा हुआ। वहीं राकांपा (शरद पवार गुट) को खुद को 'किंग मेकर' मानने में गुरेज नहीं हुआ।

इसी के बाद उत्साहित कांग्रेस ने आगे बढ़कर विधानसभा चुनाव की पिच पर खेलना आरंभ किया। बार-बार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पटोले ने राज्य विधानसभा की 288 सीटों तक पर चुनाव लड़ने की चर्चा की। हालांकि

उनकी बातों को पार्टी के राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला से लेकर हाईकमान तक ने अधिक महत्व नहीं दिया। किंतु कांग्रेस की महत्वाकांक्षा ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) को चिंता में डाल दिया। इसी के चलते दिल्ली के चक्कर लगाने में भरोसा नहीं करने वाले शिवसेना प्रमुख ठाकरे तीन दिन तक राष्ट्रीय राजधानी में न केवल रुके, बल्कि अनेक दलों के नेताओं से मिले। यद्यपि अपने दौरे में उन्हें किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला और उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से अपनी मंशा व्यक्त नहीं की।

मगर इसका मतलब यह भी नहीं रहा कि पूरी यात्रा खामोशी में ही पूरी हो गई। वैसे मेल-मुलाकातों से अलग कांग्रेस साफ कह रही है कि चुनाव से पहले किसी नेता का नाम घोषित करना उसकी परंपरा नहीं है, जिसे उसने लोकसभा चुनाव तक कायम रखा और आगे भी निभाएगी। यदि लोकसभा चुनाव के परिणामों के सापेक्ष विधानसभा चुनावों की संभावनाओं को रखा जाए तो उसमें भी कहीं न कहीं यह संकेत मिल रहे हैं कि आगे भी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और राकांपा(शरद पवार गुट) लाभ में रहेंगे। संभव है कि दोनों ही दल शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की तुलना में कुछ कम-ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन परिणामों के हिसाब से वे लाभ में रह सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यह बात शिवसेना को अच्छी तरह समझ में आ रही है। यदि वह चुनाव से पहले दबाव बनाने की स्थिति में नहीं रहेगी तो परिणामों के बाद उसकी स्थिति अधिक असहाय हो जाएगी।

वहीं दूसरी ओर यदि महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे बनते हैं तो शिवसेना (शिंदे गुट) थोड़ी मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) से राज ठाकरे पहले ही अलग और लगभग 250 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में शिवसेना का शिंदे गुट जहां-जहां ठाकरे गुट के आमने-सामने होगा, वहां-वहां उसे सहानुभूति और शिवसेना के परंपरागत मतों के नाम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि राज्य का चुनाव सीधे तौर पर ठाकरे विरुद्ध शिंदे हो जाता है तो भी महाविकास आघाड़ी को सीधा लाभ मिल सकेगा।

इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास अधिक विकल्प नहीं हैं। कुल जमा जहां महाविकास आघाड़ी शिवसेना और राकांपा के मूल नेताओं की छवि के साथ सामने आएगी, तो दूसरी ओर महागठबंधन में टूटने के बाद आए नेता दिखाई देंगे, जिन पर लोकसभा चुनाव से भी अधिक हमले किए जाएंगे।

महाविकास आघाड़ी की तरह महागठबंधन के घटक किसी चेहरे विशेष को लेकर आग्रही नहीं हैं। उनकी राजनीति समझौते से जुड़ी है। यदा-कदा गठबंधन के सहयोगी राकांपा (अजित पवार गुट) के नेता अजित पवार जरूर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री बनने का सपना सार्वजनिक कर देते हैं। किंतु उन्हें यह मालूम है कि चुनाव परिणामों के बाद उनका राजनीतिक वजन कितना होगा। इसलिए विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा फिलहाल महाविकास आघाड़ी की अपनी समस्या है, जिसे भविष्य की चिंता में शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट प्रमुखता से उभार रहा है। उसे पिछले दिनों की पार्टी की फूट से राकांपा (शरद पवार गुट) से अधिक नुकसान हुआ।

इसी कारण पिछले पचास सालों में भगवा मतों के अलावा किसी अन्य वोट का स्वप्न नहीं देखने वाली पार्टी पिछले पांच साल से धर्मनिरपेक्ष मतों की चिंता करने लगी है। वह यह मान रही है कि लोकसभा चुनाव में उसे मुस्लिम मतदाताओं ने मत दिया, जिनकी उसने पहले कभी अपेक्षा नहीं की। यहां तक कि उद्धव ठाकरे कोरोना काल में अपनी सरकार की मुस्लिमों को दी सेवाओं को भी गिनाने लगे हैं। कुछ यही वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आघाड़ी के कार्यकाल के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के फेसबुक लाइव का बार-बार जिक्र कर रहे हैं और उन्हें बंद कमरे से काम करने वाला नेता बता रहे हैं। फिलहाल चेहरा मतदाता के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। हालांकि वह राजनीति में हर एक चेहरे की अपनी चिंता कभी समझ नहीं पाएंगे।

हर घर तिरंगा और देशभक्ति की नई लहर

अभिलाष खांडेकर

प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाने की अपील के बाद 9 से 15 अगस्त के बीच देश में 'राष्ट्रवाद' की एक नई लहर देखी गई। देश के अधिकांश हिस्सों में और मुख्यत: भाजपा शासित राज्यों में, तिरंगे के इर्द-गिर्द सरकार प्रायोजित भव्य रैलियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। निस्संदेह, प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्र के प्रति बिना शर्त प्रेम और सम्मान होना चाहिए। इसलिए 'हर घर तिरंगा' अभियान एक मायने में सराहनीय है क्योंकि यह लोगों में देशभक्ति की सुप्त भावनाओं को जगाता है।

हालांकि, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों द्वारा शहर की व्यस्त सड़कों पर रैलियों का नेतृत्व करने के कारण ट्रैफिक जाम में फंसे कई नागरिक और अन्य लोग, जिन्होंने एक सप्ताह के दौरान आयोजित भव्य कार्यक्रमों को दूर से देखा, वे सोच रहे थे कि क्या राष्ट्र के प्रति प्रेम व्यक्त करने का यही एकमात्र तरीका बचा है। कई शहरों में भाजपा नेताओं की तस्वीरों वाले नए खर्चीले होर्डिंग्स लगे थे। कुछ राज्यों में, सरकारी अधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से तिरंगा खरीदने और 78 वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने घर और अपने वाहनों पर लगाने के लिए कहा गया। छोटी रैलियों के लिए स्कूली बच्चों को 'तिरंगा' दिया गया। मानव श्रृंखला बनाने सहित लोक नृत्य, चित्रकला प्रतियोगिताएं व अन्य कई गतिविधियां आयोजित की गईं। नेताओं की रैलियों का स्वागत करने के लिए सैकड़ों मंच बनाए गए। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कई दशकों से प्रत्येक सरकार द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए पारंपरिक रूप से मनाए जाते रहे हैं। लेकिन इन रैलियों के दौरान नेताओं ने लोगों से अपील की कि 'हमें लोगों को, देश को विकास के पथ पर ले जाना है और मोदीजी के नेतृत्व में भारत वास्तव में तेजी से प्रगति कर रहा है।'

लेकिन ऐसे अनुत्पादक आयोजनों से देश विकास के पथ पर कैसे अग्रसर होगा? कई साल पहले यानी जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से लोगों

में देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से इस तरह के खर्चीले आयोजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा के आलोचकों का आरोप है कि पार्टी लगातार सरकारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को इवेंट मैनेजमेंट में उलझाए हुए है, जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता जिससे लोगों, खासकर युवाओं को कोई फायदा हो। तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान को इसी संदर्भ में देखा गया।

सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते भाजपा के पास ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है जो बड़ी संख्या में इस तरह की रैलियों और कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। हम सब जानते हैं कि ये राजनीतिक कार्यकर्ता कौन हैं। भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों को देखकर लोगों को लगता होगा कि सरकारें उनके लिए कुछ करने में व्यस्त हैं।

इसके दूसरे पहलू को देखें- भारतीयों का एक बड़ा वर्ग इस बात पर हैरान था कि इस तरह के अनुत्पादक आयोजन वास्तव में कैसे लोगों की मदद करेंगे। देशभक्ति महत्वपूर्ण है लेकिन लोगों को अच्छा भोजन और पानी चाहिए; कानून का पालन करने वाला समाज और शिक्षा आदि चाहिए। मध्यम वर्ग के लोगों ने महंगे ईंधन की भारी बर्बादी, बढ़ते प्रदूषण की ओर इशारा किया जबकि गुटखा थूकने वाले, निरंकुश युवाओं को इसने झूठी उम्मीदें दीं। रैलियों में कई असामाजिक तत्वों की हुल्लड़बाजी आम आदमी को सिरदर्द की तरह ही लगी।

तो असली देशभक्त कौन है? क्या भ्रष्टाचार करने वाला देशभक्त है? क्या कर चोरी करने वाले लोग देशभक्त कहला सकते हैं, भले ही वे तिरंगा लहरा रहे हों? क्या काम से जी चुराने वाले सरकारी कर्मचारी देशभक्त हैं? क्या पुल बनाने वाले वे देशभक्त हैं, जिनके पुल बनते ही ढह जाते हैं? ऐसे जुलूसों और रैलियों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के वेश में कई छोटे-बड़े अपराधी और स्थानीय गुंडे शामिल होते हैं। क्या उन्हें देशभक्तों में शामिल करना चाहिए?

एक समय था जब सिनेमा हॉल में फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद राष्ट्रगान बजाया जाता था, लेकिन कई लोग खड़े नहीं होते थे या हॉल से बाहर चले जाते थे। फिर ज्यादातर हॉल मालिकों ने राष्ट्रगान बजाना बंद कर दिया क्योंकि ऐसा करने से राष्ट्रगान का अपमान होता था। इस पर काफी बहस हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जिसने पहले तो इसे अनिवार्य बना दिया लेकिन फिर इसमें संशोधन कर इसे वैकल्पिक बना दिया।

मैं तिरंगे का सम्मान करने के बिलकुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अनुत्पादक आयोजनों पर भारी मात्रा में सार्वजनिक धन क्यों खर्च किया जाए? उन परेशान लोगों में से कई की तरह, मुझे भी खुशी होती अगर राजनीतिक नेता और उनके अनुयायी ऐसी रैलियों के बजाय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली अनगिनत गलत चीजों को सुधारने में मदद करते।

हमें अराजकता से आजादी चाहिए; बेरोजगारी से आजादी चाहिए। अगर पिछले दशक में शिक्षा के स्तर में वास्तव में सुधार हुआ होता, बेहतर स्कूली शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होतीं और अच्छे संस्थान बने होते, साथ ही अगर भारत में सांप्रदायिक नफरत कम हुई होती और महिलाओं की सुरक्षा हुई होती तो 78 वें स्वतंत्रता दिवस को वाकई अच्छे से मनाया जा सकता था।

शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग होगी कठिन चुनौती

शोभना जैन

बांग्लादेश में गत पांच अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद हसीना के धुर विरोधी रहे बांग्लादेश के नोबल पुरस्कार प्राप्त 84 वर्षीय अर्थशास्त्री डॉ। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन देश में नई सरकार को शुरुआत से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सरकार ने ऐसे समय में कार्यभार संभाला है, जब देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चरमरा चुकी है। अल्पसंख्यकों के ठिकानों, मंदिरों पर हमले जारी हैं, भारत-बांग्लादेश सीमा पर भारी तनाव है, वहां बसे हिंदू भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। उधर हसीना इस्तीफे के बाद पांच अगस्त से भारत में अस्थाई रूप से रह रही हैं, अलबत्ता उन्होंने भारत से राजनैतिक शरण नहीं मांगी है। उनके सहयोगियों की धरपकड़ जारी है। लेकिन इस

अराजकता के बीच अब एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में खबर आई है कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार हत्या के आरोपों को लेकर हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। अगर बांग्लादेश सरकार भारत से इस आशय की मांग करती है तो भारत की प्रगाढ़ मित्र रही हसीना को लेकर भारत के लिए निश्चय ही दुविधा की स्थिति होगी। ऐसी स्थिति आने पर भारत क्या फैसला करेगा? हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में ही फिलहाल अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई मांग फिलहाल आई नहीं है लेकिन दो देशों के बीच भावनात्मक संबंधों पर डिप्लोमेसी, राष्ट्रीय हित सदैव हावी रहते हैं। हालांकि इस सब के बावजूद ऐसे मामलों में डिप्लोमेसी के साथ मानवीय पहलू भी जुड़ा रहता है। संभवत: इसी के मद्देनजर भारत को हसीना के साथ अपने प्रगाढ़ संबंधों के साथ ही अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए बांग्लादेश की नई सरकार के साथ अपने संबंधों को सर्वोपरि रखना होगा। इस सबके मद्देनजर यह भारत के लिए एक कठिन फैसला होगा। दोनों देशों के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि तो हो चुकी है लेकिन इसमें राजनैतिक बंदियों को लेने का कोई प्रावधान नहीं है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल एम। खान का कहना है कि इसी प्रावधान के चलते संभवत: प्रत्यर्पण हसीना पर लागू नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 1975 में बांग्लादेश के जनक और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान और उनके दस वर्षीय बेटे सहित परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त जर्मनी में रह रही हसीना ने जब भारत से राजनैतिक शरण मांगी तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हसीना के भारत आने पर फौरन उनसे मिलने गईं और उन्हें भारत में सुरक्षा मुहैया कराई और रहने को आवास भी दिया। हसीना के भारत की मोदी सरकार के साथ भी अच्छे रिश्ते रहे। हाल ही में अपनी चीन यात्रा से वे बीच में ही लौट आई थीं और महत्वाकांक्षी तीस्ता नदी जल परियोजना भारत को दिए जाने की घोषणा की थी। निश्चय ही भारत और बांग्लादेश के प्रगाढ़ संबंधों के लिए आपसी समझबूझ का यह एक अच्छा फैसला रहा।

देखकर खुशी है कि लोग मुझे याद कर रहे हैं

दिव्येंदु शर्मा नए वेब शोज के साथ लौट चुके हैं। उनकी सीरीज लाइफ हिल गई हअअ पर रिलीज हो गई है। इसमें उनके साथ कुशा कपिला भी लीड किरदार में हैं। इस सीरीज को बनाया है आरुषि निशंक ने। शो में डांस कोरियोग्राफर मुक्ति मोहन का भी रोल हैं। दिव्येंदु ने इसी बीच मिर्जापुर के अपने फेमस किरदार मुन्ना त्रिपाठी पर बात की। दिव्येंदु शर्मा ने कहा कि लोग अभी भी उनसे मिर्जापुर को लेकर सवाल करते हैं। मुन्ना को मरते हुए दिखाया है, फिर भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सीजन में कैसे भी करके उसकी वापसी हो जाए। मैं बहुत खुश हूं कि लोग मेरे कैरेक्टर को इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे न देखकर लोगों का दिल दुखा है। दिव्येंदु ने कहा कि मिर्जापुर के पहले सीजन का वो डायलॉग, 'बहुत तकलीफ होती है, जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता न समझे' रियल लाइफ में भी फील होता है। एक आर्टिस्ट के जीवन में ऐसे मोमेंट बहुत आते हैं।

स्क्रिप्ट पढ़ते ही काम करने का मन कर गया

दिव्येंदु ने लाइफ हिल गई में अपने किरदार पर बात करते हुए कहा, 'इस सीरीज का मुद्दा कोई बहुत ज्वलंत नहीं है। यहां बस जीवन जीने की बात दिखाई गई है। हम साधारण जीवन में कैसे रहते हैं। क्या बेसिक परेशानियां होती हैं, उनसे डील कैसे करते हैं। मैं पहली बार एक शहरी लड़के का किरदार निभा रहा हूं। स्क्रिप्ट ऐसी थी कि पढ़ने के दौरान ही इसमें काम करने की इच्छा हो गई। एक तरह से देखा जाए तो पहली बार भाई-बहन के रिश्ते पर कोई शो बना है।'

कबीर बहिया के साथ शादी करने वाली हैं कृति? अभिनेत्री ने तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म दो पत्ती को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इससे पहले उन्होंने इस साल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक रोबोट का किरदार निभाया था। अभिनेत्री अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। अब हाल ही में, कृति ने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ अपनी डेटिंग अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है। आइए जानते हैं कि अभिनेत्री ने क्या कहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन हाल ही में, अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ छुट्टियों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने के बाद चर्चा में थीं। अब अभिनेत्री ने उनके बारे में लिखी गई ऑनलाइन खबरों पर प्रतिक्रिया दी हैं और इसे निराशाजनक बताया है। कृति और कबीर की तस्वीरें वायरल होने के बाद, कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अभिनेत्री जल्द ही शादी करने की योजना बना रही हैं। हालांकि, कृति जल्द ही शादी करने के मूड में नहीं हैं और उन्होंने इन खबरों को बेहद परेशान करने वाला बताया है। अब हाल ही में, फिल्मफेयर के साथ एक साक्षात्कार में अभिनेत्री ने बताया कि जब उनके बारे में गलत जानकारी फैसाई जाती है तो यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला होता है। इसलिए क्योंकि इसका असर उनके परिवार पर भी पड़ता है। कृति ने कहा, उन्हें किसी झूठी बात के दुष्परिणामों से नहीं जूझना चाहिए। यह तब और भी अधिक परेशान करने वाला होता है, जब अफवाहें मेरी निजी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। फिर दोस्त मुझे मैसेज भेजते हैं कि क्या यह सच है और मुझे क्लियर करना पड़ता है कि यह सच नहीं है। उन्होंने आगे कहा, लोग अक्सर कहानियां फैलाने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने की जहमत नहीं उठाते, खासकर सोशल मीडिया पर जहां नेगेटिविटी तेजी से फैलती है। इन झूठों को लगातार सही करना परेशान करने वाला है और किसी भी और चीज से ज्यादा परेशान करने वाला होता है।

कीर्ति ने ठुकराया था कल्कि 2898 एडी का ऑफर?

साउथ फिल्मों की खूबसूरत और बेहद उम्दा अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने फिल्म कल्कि 2898 एडी के लाखों प्रशंसक हैं। कीर्ति ने कई फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि कल्कि 2898 एडी में कीर्ति ने एक मुख्य भूमिका का ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन बुज्जी के किरदार को अपनाकर उन्होंने आज सभी का दिल जीत लिया है। वैसे कीर्ति इन दिनों अपनी आगामी तमिल फिल्म रघु थाथा के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं। बता दें कि कीर्ति अभिनित फिल्म रघु थाथा इस स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कीर्ति ने फिल्म कल्कि 2898 एडी में अपनी भूमिका को लेकर बात की। कीर्ति भी फिल्म कल्कि 2898 एडी का हिस्सा थीं। इस फिल्म में कीर्ति ने प्रभास की बुज्जी को अपनी आवाज दी थी। हालांकि, फिल्म कल्कि 2898 एडी की स्क्रीनिंग के दौरान कीर्ति कहीं नजर नहीं आई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कीर्ति ने बताया कि उन्हें निर्देशक नाग अश्विन ने शुरू में एक अलग भूमिका की पेशकश की थी, लेकिन कीर्ति ने उस किरदार के लिए उन्हें मना कर दिया था। कीर्ति को जो ऑफर दिया जा रहा था, वह उससे संतुष्ट नहीं थीं। इसलिए जब नाग अश्विन ने उन्हें बुज्जी की आवाज देने का सुझाव दिया, तब उन्होंने इसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया। बुज्जी की आवाज की भूमिका में कीर्ति की खूब प्रशंसा हुई है।

वॉर 2 के लिए ऋतिक ने सीखा जापानी तलवार कताना चलाना

वॉर 2 अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन इस फिल्म को लेकर दर्शकों में अभी से काफी ज्यादा उत्साह है। यशराज स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म में ऋतिक के साथ जूनियर एनटीआर भी नजर आने वाले हैं। यह उनकी पहली हिंदी फिल्म है। यही वजह है कि दक्षिण भारत के लोगों को भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। वॉर 2 का फिल्मांकन काफी समय पहले शुरू किया जा चुका है। हालांकि, निर्माता बहुत हद तक शूटिंग से जुड़ी चीजों को गोपनीय रखने में कामयाब रहे हैं। इस बीच हाल ही में इस फिल्म को लेकर कुछ दिलचस्प जानकारी सामने आई हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में ऋतिक रोशन का एंट्री सीन कुछ ऐसा होगा जो दर्शकों की सांसें रोक देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक जापानी मठ में एक खतरनाक खलनायक के साथ तलवारबाजी करते नजर आएंगे। पहले खबर थी कि ऋतिक शाओलिन मंदिर में एक एक्शन सीन करेंगे, लेकिन अब खबर है कि फिल्म में यह उनका इंट्रोडक्शन सीक्वेंस होगा। इस सीन को मार्च में शूट किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स से यह भी पता चला है कि फिल्म के लिए ऋतिक रोशन ने न केवल हफ्तों तक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया, बल्कि जापानी तलवार कताना चलाना भी सीखा। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि वॉर के गाने जय जय शिव शंकर की तरह फिल्म के सीक्वल में भी एक गाना होगा, जिसमें जूनियर एनटीआर और ऋतिक थिरकते हुए दिखेंगे।

फिल्मों की आलोचनाओं से कैसे निपटते हैं अक्षय कुमार

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म खेल खेल में को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म अक्की के साथ वाणी कपूर, तापसी पन्नू, एमी विर्क और फरदीन खान समेत कई सितारे नजर आएंगे। बॉक्स ऑफिस पर लंबे वक्त से अक्षय कुमार की फिल्में असफल साबित हो रहीं हैं। हाल ही में अभिनेता ने बताया कि वह अपनी फिल्मों के लिए मिलने वाली आलोचनाओं से कैसे निपटते हैं। अक्षय कुमार ने एक बातचीत के दौरान कहा, इंसान का बैकग्राउंड क्या है, उसने जीवन में क्या किया है? यह एक व्यक्तिगत आलोचना है, जहां लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं। एक वह इंसान होता है जो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति बेहतर हो, जो वह अपने दिल से कह रहा होता है। इसलिए मुझे वह पसंद है, जिसे मैं बहुत सही तरीके से लेता हूं। मैंने आलोचना के कारण भी कई बदलाव किए हैं। मैं जब सही आलोचना सुनता हूं और इसे समझता हूं, तो वो करता भी हूं। उन्होंने आगे कहा, लोग जो भी कहते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए। अभिनेता ने आगे कहा, मैं अलग-अलग तरह की फिल्में करना भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे दर्शकों को वही देना चाहिए जो वे चाहते हैं। अक्षय ने फिल्म खेल खेल में की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा किया कि उन्हें अपनी फ्लॉप फिल्मों के लिए शोक संदेश मिल रहे हैं।

छोटी उम्र में सारा अली खान ने कमाया बड़ा नाम

सारा अली खान बॉलीवुड की उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक हैं। बहुत कम समय में अभिनेत्री ने खुद को एक अच्छी हीरोइन के रूप में इंडस्ट्री में स्थापित कर लिया है। छोटी उम्र में ही सारा लाखों लोगों की पसंदीदा बन चुकी हैं। अभिनेत्री अपना जन्मदिन मना रही हैं। अभिनेत्री का जन्म 12 अगस्त 1995 को मुंबई में हुआ। वह दिग्गज अभिनेता सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह साल 2004 में एक-दूसरे से अलग हो गए और सारा की देखभाल उनकी मां अभिनेत्री अमृता ने की। सारा अली खान ने फिल्मों में आने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी की। वह बॉलीवुड की पढ़ी-लिखी अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने अपनी शुरूआती पढ़ाई मुंबई के बेसेंट मोंटेसरी स्कूल से की। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए 2016 में न्यूयॉर्क चली गईं, वहां से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। सारा अली खान ने साल 2018 में आई फिल्म केदारनाथ से डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नजर आएं। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद वह रणवीर सिंह के साथ 'सिंबा' में नजर आईं, फिर 'वह लव आजकल', 'अतरंगी रे', 'कूली नंबर 1', 'गैसलाइट', 'जरा हटके जरा बचके', 'मर्डर मुबारक', 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में दिखीं। हाल ही में उन्हें उनकी फिल्म 'ऐ वतन मेरे वतन' में देखा गया। उनकी आगामी फिल्मों की बात करें तो वह अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' और 'मेट्रो इन दिनों' में नजर आ सकती हैं। सारा अली खान जहां एक तरफ पटौदी खानदान से ताल्लुक रखती हैं, वहीं, वह खुद भी करोड़ों की मालकिन हैं। उन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ कई हिट फिल्में की हैं। वह छोटी सी उम्र में ही लग्जरी लाइफ जीती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 41 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं। सारा अली खान के फिल्मों की फीस की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपनी एक फिल्म के लिए पांच से सात करोड़ रुपये चार्ज करती हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सारा ने मुंबई में एक घर भी खरीदा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके घर की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये है।

12वीं फेल से चमके विक्रांत मैसी फिर आई हसीन दिलरुबा समेत इन फिल्मों से जीता फैंस का दिल

अभिनेता विक्रांत मैसी इन दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अपनी फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इसके साथ ही विक्रांत मैसी की दमदार अदाकारी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। विक्रांत ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक का लंबा सफर तय किया है। इस दौरान उन्होंने कई टीवी शोज, वेब सीरीज और और फिल्मों में काम किया। वहीं अब उन्हें अपने काम की खूब तारीफें सुनने मिलती हैं। दरअसल, फिल्म 12वीं फेल अभिनेता के करियर में मील का पत्थर साबित हुई, जिसने उनके करियर ग्राफ को बढ़ा दिया। ऐसे में चलिए जानते हैं विक्रांत की कुछ दमदार फिल्मों के बारे में।

फिर आई हसीन दिलरुबा

फिर आई हसीन दिलरुबा विक्रांत की रिलीज हुई सबसे ताजा फिल्म है, जो आज ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। फिल्म में विक्रांत ने रिशु का किरदार निभाया है, जो अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी को बचाने की कोशिश करता है। फिल्म में उनके साथ तापसी पन्नू और सनी कौशल भी नजर आए हैं। विक्रांत ने इस फिल्म में भी दमदार अदाकारी दिखा दर्शकों को दीवाना बना दिया।

12वीं फेल

12वीं फेल विक्रांत मैसी की बड़ी जीत के रूप में सामने आई है, जिसने अपनी दमदार कहानी और प्रदर्शन के लिए खूब प्रशंसा बटोरी। 12वीं फेल का निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा ने किया है और फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने इसे सह-निर्मित किया है। फिल्म में विक्रांत मैसी ने संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हैं, क्योंकि वे शैक्षणिक असफलताओं का अनुभव करने के बाद जीवन में आगे बढ़ते हैं।

हसीन दिलरुबा

हसीन दिलरुबा में विक्रांत मैसी, तापसी पन्नू और हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं। यह विनील मैथ्यू द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और 2021 में रिलीज हुई थी। विक्रांत ने रिशु को एक सौम्य व्यक्ति के रूप में पेश किया, जो खुद को प्यार, विश्वासघात और संदेह के जाल में उलझा हुआ पाता है।

ए डेथ इन द गंज

फिल्म ए डेथ इन द गंज कोंकणा सेन शर्मा द्वारा निर्देशित एक मनोरंजक ड्रामा फिल्म है। 2016 में रिलीज हुई यह उनकी पहली निर्देशित फिल्म है और इसमें विक्रांत मैसी, कल्कि कोचलिन, रणवीर शौरी और अन्य कलाकारों ने काम किया है। कहानी 1970 के दशक में सेट की गई है और एक पारिवारिक छुट्टी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो झारखंड के मैक्लुस्कीगंज में उनके पैतृक घर में अप्रत्याशित घटनाओं के सामने आने पर एक अंधेरे मोड़ पर आ जाती है।

छपाक

मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित मार्मिक ड्रामा फिल्म छपाक 2020 में रिलीज हुई थी। इसमें दीपिका पादुकोण ने मालती की भूमिका निभाई है, जो वास्तविक जीवन की एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल से प्रेरित है। विक्रांत मैसी ने अमोल की भूमिका निभाई है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो मालती को न्याय और सशक्तिकरण की लड़ाई में मदद करता है। यह फिल्म मालती के साहस की यात्रा को दर्शाती है, क्योंकि वह जघन्य हमले के बाद की स्थिति से निपटती है, कई सर्जरी से गुजरती है और अपने जीवन को फिर से बनाने का प्रयास करती है।

फरदीन खान की वापसी पर तापसी पन्नू ने दी शुभकामनाएं

तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में हैं उनकी हालिया रिलीज फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा को काफी सराहा जा रहा है। इस फिल्म में वह विक्रांत मैसी, सनी कौशल और जिमी शेरगिल के साथ नजर आ रही हैं। दर्शकों को इनकी केमिस्ट्री काफी पसंद भी आ रही है। इसके अलावा वह अपनी आगामी मल्टी स्टारर फिल्म खेल खेल में को लेकर भी चर्चा में हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, एमी विर्क आदि कई कलाकार नजर आने वाले हैं। तापसी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने सह-कलाकार की वापसी को लेकर शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

युवाओं के भविष्य के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़ : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेला के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में युवाओं को नियुक्ति-पत्र, विभिन्न योजनाओं के पात्रों को ऋण और विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में बोले रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 साल पहले उत्तर प्रदेश को भारत का डार्क स्पॉट माना जाता था। आज यूपी एक उजला स्थान बन गया है और भारत के विकास में अपना योगदान देने में सबसे आगे है। यहां दंगे और अराजकता थी, माफिया हावी थे, बेटियां और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। उन्होंने कहा कि आज यूपी निवेश के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। हम किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे।

उप्र सरकार ने निष्पक्षता से काम नहीं किया : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नयी चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का शनिवार को स्वागत किया। मायावती ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से साबित होता है कि राज्य सरकार ने अपना काम निष्पक्षता से नहीं किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यार्थियों की चयन सूची को रद्द करके तीन महीने के भीतर नयी सूची बनाने के उच्च न्यायालय के फैसले से साबित होता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया। इस मामले में पीड़ितों, खासकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। बसपा प्रमुख ने कहा, वैसे भी सरकारी पदों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की काफी आलोचना हो रही है।

मुडा मामले में सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा

बेंगलूरू। मुडा मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुरी तरह फंस गए हैं। भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब राज्यपाल ने भी सीएम के खिलाफ मुडा मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बीते दिनों रूड्ड (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) के कथित भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कैबिनेट की राय मांगी थी। जिसके बाद गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी गई। साथ ही मंत्रिपरिषद ने इसे बहुमत से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दिया। हालांकि राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में राय ली। जिसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। शिकायत में सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, बेटे और मुडा के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

ममता बनर्जी के मार्च पर भाजपा का तंज

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की विरोध रैली को लेकर उन पर कटाक्ष किया और पूछा कि मुख्यमंत्री किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि वह स्वयं राज्य की मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने टीएमसी सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि वह (ममता बनर्जी) खुद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर वह किसके खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं? मजूमदार ने आगे कहा कि बनर्जी की सरकार निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के बजाय इस जघन्य अपराध पर राजनीति कर रही है। उन्होंने टीएमसी पर न्याय मांगने वाली भाजपा को रोकने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।

पहली बार मतदान करेंगे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही केंद्रशासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। अधिकारियों ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू होंगे, जिसमें सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित किसी भी घोषणा या नीतिगत निर्णय के संबंध में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। हम आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की। इससे 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किये जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए सरकार चुनने का मंच तैयार हो गया है। इन चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी पहली बार मतदान करेंगे।

देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर

24 घंटे तक बंद रही हर स्वास्थ्य सेवा, बेहाल हुए मरीज

नईदिल्ली। कोलकाता में आठ और नौ अगस्त के रात को आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए विभत्स कांड के बाद देश भर में मेडिकल फ्रेटरनिटी में रोष है। इसी के चलते 17 अगस्त को देश भर में डॉक्टर की हड़ताल है। इंसाफ की मांग करते हुए डॉक्टर देश भर में मार्च से लेकर प्रदर्शन कर रहे है। इंसाफ के लिए ही 17 अगस्त को आईएमए के आह्वान पर देश भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं से लेकर ऑपरेशन तक स्थगित किए गए है। आईएमए में सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद रखने का फैसला किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। इससे एक दिन पहले फोर्डा ने भी हड़ताल का ऐलान किया है।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या मामले के खिलाफ डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल पर सायन अस्पताल के एक मरीज के रिश्तेदार ने कहा, हमारा मरीज आईसीयू में है। सेवाएं उचित हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कोलकाता में जो हुआ वह गलत है। जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। सरकार और लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए। अस्पताल में सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं।

रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यूसीएमएस (यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज) और जीटीबीएच (गुरु तेग बहादुर अस्पताल) ने भी ऐलान किया है कि उनकी हड़ताल शनिवार को भी जारी रहेगी। सुबह 9.30 बजे उनकी आम सभा होगी। हड़ताल के तहत ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट), वैकल्पिक सेवाएं, प्रयोगशाला और लैब सेवाएं बंद रहेंगी।

तमिलनाडु के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ चेन्नई में बहिष्कार विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं, ...आईएमए अधिसूचना के अनुसार, हम अपनी सभी वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार करने जा रहे हैं। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। हम केवल पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं... एक सप्ताह हो गया है, लेकिन मामले में कोई गंभीर जांच नहीं की गई है। कुछ बलि के बकरे गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन असली अपराधी अभी भी बाहर हैं।

इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में भी डॉक्टर के बलात्कार-हत्या की घटना के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) में विरोध प्रदर्शन किया।

उच्च न्यायालय ने कोलकाता के एक अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और उसकी हत्या तथा वहां तोड़फोड़ के विरोध में यहां के चिकित्सकों द्वारा 17 अगस्त को आहूत हड़ताल पर शुक्रवार को राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की खंडपीठ ने नरसिंहपुर जिले के अंशुल तिवारी द्वारा हड़ताल को चुनौती देने वाली याचिका पर भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के डीन, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और अन्य को नोटिस जारी किए। मामले की अगली सुनवाई आज होगी।

'ग्लोबल साउथ' सम्मेलन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का मंच बना : मोदी

प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर मोहम्मद यूनुस ने की शिरकत, प्रधानमंत्री ने संबोधन में उठाए ये मुद्दे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में 17 अगस्त को तीसरी ग्लोबल साउथ समिट में बांग्लादेश की तरफ से अंतरिम पीएम मोहम्मद युनुस शामिल हुए हैं। शुक्रवार को ही पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच हुई थी फोन पर बात। बांग्लादेश में सत्ता बदल के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के नेता एक साथ किसी मंच पर नर आ रहे हैं। भारत ने जी20 की अध्यक्षता मिलने पर दुनिया के विकाशसील देशों की आवाज मजबूत करने के लिए ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत की थी। भारत ने सितंबर 2023 में हुए जी20 शिखर सम्मेलन में भी पुरजोर तरीके से ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले पिछड़े और विकासशील देशों की आवाज बुलंद की थी। भारत की अगुवाई में तीसरी बार यह वर्चुअल शिखर बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रमुख भाग ले रहे हैं।

ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह एक ऐसा मंच बना, जहां हमने विकास से संबंधित समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत ने ग्लोबल साउथ की आशाओं, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित जी-20 एजेंडा तैयार किया।

पीएम मोदी ने कहा, जब भारत ने जी-20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने संकल्प लिया था कि हम जी-20 को एक नया स्वरूप देंगे। उन्होंने आगे कहा, हम ऐसे समय में मिल रहे हैं, जब दुनिया अनिश्चितता में जी रही है। युद्ध जैसी

स्थितियों ने हमारी विकास यात्रा में चुनौतियां बढ़ा दी है। हम पहले से ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य, भोजन और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। आतंकवाद उग्रवाद और अलगाववाद हमारे समाज के लिए गंभीर खतरा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वह समय है, जब ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक-दूसरे की ताकत बनें। हमें एक-दूसरे के अनुभव से सीखना होगा और एक-दूसरे की क्षमताओं को साझा करना होगा। भारत ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग करने और अपने अनुभवों और क्षमताओं को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम व्यापार, समावेशी विकास, एसडीजी की प्रगति और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं।

पीएम मोदी ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर उनका उनका मिशन एक विश्व, एक स्वास्थ्य और दृष्टिकोण आरोग्य मैत्री, जिसका मतलब है स्वास्थ्य के लिए मित्रता। मानवीय संकट के दौरान भारत अपने मित्र देशों की मदद सबसे पहले करता है।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोलकाता जाएंगे क्या : भाजपा

नईदिल्ली। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बर्बरतापूर्वक बलात्कार किए जाने के बाद पूरा देश हिल गया है। पूरे देश में चिकित्सा जगत जांच में त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर है। पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इन सबके बीच भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं कि आप घोटालेबाजों को बचाने के लिए तो बेंगलुरु चले गए, लेकिन आप कोलकाता जाएंगे क्या?

इससे साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं... तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोलकाता जाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने संविधान को बनाए रखने की शपथ ली थी, लेकिन हम सभी ने देखा है कि वे कितना बड़ा

हंगामा मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन सरकार के तहत स्थिति बहुत खराब है।इससे पहले शहजाद पूनावाला ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की विभत्स गैंगरेप और हत्या को लेकर पूरा भारतवर्ष आक्रोशित है। सभी लोगों की एक ही मांग है कि न्याय होना चाहिए। लेकिन न्याय देने के बदले टीएमसी सरकार का एजेंडा बन चुका है- न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ... केवल और केवल बलात्कारी बचाओ।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीत सरकार का एकमात्र एजेंडा ''सच को चुप करना, बलात्कारियों को बचाना और किसी भी कीमत पर सबूत नष्ट करना'' है। उन्होंने कहा कि यह दोषियों को बचाने की ''सबसे भयावह एवं संस्थागत लीपापोती'' है। पूनावाला ने पत्रकारों से कहा कि न्याय के लिए आवाज उठाने पर 43 चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया, जिनमें से कुछ का तबादला दूरदराज के इलाकों में किया गया है जबकि पुलिस ने नागरिकों और पत्रकारों को न्याय के उनके धर्मयुद्ध के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

खेल
प्रमुख समाचार

विनेश फोगाट का नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत

नई दिल्ली। भारत की दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट पेरिस से भारत लौट आई हैं। उनका नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। विनेश के स्वागत के लिए फैंस ढोल नगाड़ों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं, पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक भी एयरपोर्ट पर नजर आए। उनसे मिलते ही विनेश भावुक हो गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। विनेश का गांव पहुंचने तक 20 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। विनेश पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गई थीं। महिलाओं की 50 किग्रा वर्ग के फाइनल में पहुंचने के बाद उन्हें बढ़े हुए वजन की वजह से डिसक्वालिफाई कर दिया गया था।

लोगों ने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विनेश को कंधे पर उठा लिया और कंधे पर उठाकर ही गाड़ी तक ले गए। इस दौरान भी विनेश का आंसू नहीं रुके। वह गाड़ी पर बजरंग और साक्षी के साथ खड़ी हुई और रोती रहीं। विनेश ने कहा कि मैं पूरे देशवासियों को धन्यवाद कहती हूं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं।

वहीं, पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, विनेश ने देश के लिए जो किया है, वह बहुत कम लोग कर सकते हैं। उन्हें और अधिक सम्मान और सराहना मिलनी चाहिए। उन्होंने पदक के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।% वहीं, बजरंग पूनिया ने कहा- देशवासी उन्हें जबरदस्त प्यार दे रहे हैं। आप देख सकते हैं देश ने उनका किस तरह स्वागत किया गया है। दरअसल. विनेश पेरिस में पदक से चूक गई थीं। उनका वजन फाइनल से पहले 100 ग्राम ज्यादा रहा था, जिसके बाद उन्हें डिसक्वालिफाई कर दिया गया था। फिर विनेश ने खेल पंचाट में भी संयुक्त रजत पदक देने की अपील की थी, लेकिन खेल पंचाट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। पदक न जीत पाने से दुखी विनेश ने कुश्ती से संन्यास का एलान कर दिया था। यह उनका तीसरा ओलंपिक था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

भारत पूरे विश्व की मदद कर रहा : बिल गेट्स

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और अरबपति कारोबारी बिल गेट्स अमेरिका के सिएटल क्षेत्र में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर आयोजिक एक समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षित टीकों के निर्माण से लेकर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक भारत की सरलता न केवल भारतीयों, बल्कि पूरे विश्व की मदद कर रही है। गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स ने 78वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में पहले भारत दिवस समारोह को हरी झंडी दिखाई। समारोह में गेट्स ने भारत को प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में सफल नवाचारों वाला वैश्विक नेता बताया। गेट्स ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश अपने डीपीआई सिस्टम बनाने के लिए भारत के अनुभव का लाभ उठा रहे हैं।

देश में उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती

नई दिल्ली। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 4,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया है। यह टैक्स शनिवार से लागू हो गया। यह टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 17 अगस्त से प्रभावी हैं। भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया, जो उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं। पिछले दो हफ्तों में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है। भारत ने देश से अनूठे कृषि उत्पादों के शिपमेंट को बढ़ाने की अपनी पहल के तहत पोलैंड को अंजीर के रस की पहली खेप का निर्यात किया।

त्योहारों से पहले चना और चना दाल के भाव बढ़े

मुंबई। त्योहारी सीजन के पहले चना और चनादाल के भाव में उछाल देखने को मिला है, इसके भाव में अभी तक 10 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। जबकि जून में दालों की महंगाई दर 21 प्रतिशत के पार पहुंच गई थी। हालांकि जुलाई महीने में रिटेल महंगाई सालाना आधार पर घटकर 3.54 प्रतिशत पर आ गई है। इससे पहले जून में महंगाई दर 5.08 प्रतिशत पर रही थी। बावजूद इसके दालों के भाव 12 महीनों से दोहरे अंकों में बने हुए हैं और नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। त्योहारी सीजन से पहले चना दाल का भाव अभी तक 10 प्रतिशत तक बढ़ गया है। थाली में चना दाल के अलावा चने का इस्तेमाल त्योहारों में बेसने रूप में अधिक होता है जिसमें मिठाई, नमकीन और अन्य खाद्य वस्तुएं प्रमुख है। इसकी वजह से आम लोगों के जेब पर असर पड़ सकता है। उद्योग के अनुसार खुदरा बाजार में गत महीने तक 80 से 85 रुपये के बीच बिक रहा था वह आज 90 से 95 रुपये में बिक रहा है।

अंबुजा सीमेंट ने पेन्ना सीमेंट का किया अधिग्रहण पूरा

नई दिल्ली। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने देश के दक्षिणी हिस्से में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अडानी की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज के साथ अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ ही पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज अब अंबुजा सीमेंट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है। बता दें कि अंबुजा सीमेंट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जून में पेन्ना सीमेंट में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी थी। यह सौदा 10422 करोड़ रुपये में हुआ था। पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज साउथ की बड़ी कंपनी है। इस अधिग्रहण के पूरा होने के बाद माना जा रहा है कि अडानी साउथ में भी अपने कारोबार की पकड़ मजबूत करेगी। इस अधिग्रहण के पूरा होने के बाद पूरे भारत के सीमेंट बाजार में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी दो बढ़ गई है। वहीं दक्षिण भारत में हिस्सेदारी में 8 फीसदी का इजाफा हुआ है।

नीतिगत उपाय पूरा करेंगे विकसित भारत का सपना

एम गोविंद राव

केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद मचा शोरगुल थम चुका है और अब सधी नजर से देखना होगा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए मध्यम और दीर्घ अवधि में क्या रणनीति अपनानी होंगी और नीतिगत स्तर पर क्या प्रयास करने होंगे। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किसी विकसित देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 14,005 डॉलर है।

भारत की जीएनआई 2,600 डॉलर के करीब रहने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि यह विकसित देशों के समूह में इतनी जल्दी शामिल नहीं होने जा रहा है। भारत को इस समूह में आना है तो उसे प्रति व्यक्ति जीएनआई 5.3 गुना बढ़ानी होगी। दूसरे शब्दों में उसे अगले 23 वर्ष तक प्रति व्यक्ति जीएनआई में औसतन 7.5 प्रतिशत सालाना और कुल जीएनआई में औसतन 9 प्रतिशत सालाना वृद्धि करनी होगी।

एक और बात यह है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में ठहराव वर्ष 2045 में आएगा। आर्थिक समीक्षा में दिए गए अनुमानों के अनुसार कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में वर्ष 2030 तक सालाना लगभग 80 लाख नए रोजगार सृजित करने होंगे। इन दोनों पहलुओं के साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे पूरा करने के लिए यानी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद कर हरित ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ने के लिए उसे भारीभरकम निवेश करना होगा।

आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने के लिए निवेश और उत्पादन में बड़े स्तर पर वृद्धि करनी होगी। फिलहाल वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात 5 है, जिसके हिसाब से निवेश दर

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 40 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए, जो अभी 34 प्रतिशत ही है। इसमें जो कसर रह जाएगी, उसकी भरपाई उत्पादकता बढ़ाकर करनी होगी। लिहाजा नई तकनीक का इस्तेमाल करना और कार्यबल को अधिक शिक्षित एवं हुनरमंद बनाना समान रूप से जरूरी है। ये कठिन चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए प्राथमिकताएं दोबारा तय करनी होंगी और नीतिगत सुधार अविलंब लागू करने होंगे।

जुलाई में पेश केंद्रीय बजट में नौ क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताएं परिभाषित कर वृहद निर्देशों का उल्लेख किया गया है। ये प्राथमिकताएं हैं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता बढ़ाना, रोजगार एवं कौशल विकास, मानव संसाधन विकास, आधारभूत संरचना, उद्योग एवं सेवाएं, शहरी विकास, नवाचार और नई पीढ़ी के सुधार। ये व्यापक प्राथमिकताएं हैं किंतु इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिए सुधार के विशिष्ट उपाय करना जरूरी है। इन प्राथमिकताओं एवं नीतिगत संकेतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने से सही मार्ग चुनने एवं आवश्यक सुधार एवं बदलाव करने में सहायता मिलेगी।

निवेश एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है कारोबार के लिए सस्ती पूंजी उपलब्ध कराना और प्रत्यक्ष लाभ के साथ अप्रत्यक्ष लाभ भी सुनिश्चित करना होगा। वर्ष 2021-22 से ही राजकोष को मजबूत करने और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक रोकना कठिन नहीं होगा किंतु इसे और कम कर 3 प्रतिशत के मूल लक्ष्य तक लाना तथा केंद्र सरकार पर कर्ज बोझ को जीडीपी के 40 प्रतिशत तक रोकना जरूरी है ताकि निजी क्षेत्र के लिए भी कर्ज लेने की गुंजाइश बनी रहे।

यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि घरेलू बचत कम होकर 5.3 प्रतिशत रह गई है। इसे देखते हुए सरकार को मध्यम अवधि की राजकोषीय योजनाओं से जुड़े लक्ष्यों पर दोबारा विचार करना चाहिए और उन्हें अगले बजट में प्रस्तुत करना चाहिए। अगला बजट बमुश्किल छह महीने में आना है। वित्तीय क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने और सरकारी उधारी में ज्यादा अनुशासन लाने के लिए सांविधिक तरलता अनुपात में कमी करना भी इतना ही जरूरी है।

केंद्रीय मंत्री ने रायपुर में दिव्यांगजन पार्क निर्माण की घोषणा की

मुख्यमंत्री साय ने राजधानी रायपुर में 'दिव्यांगजन पार्क' निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की

कि कला मेला, दिव्यांग भाई-बहनों के अद्वितीय कौशल और उद्यमशीलता का उत्कृष्ट प्रदर्शनः डॉ. वीरेंद्र कुमार

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार और मुख्यमंत्री साय ने 'दिव्य कला मेला' का किया शुभारंभ

रायपुर। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में 17वें 'दिव्य कला मेला' का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने रायपुर में जमीन मिलने पर दिव्यांगजन पार्क निर्माण कराने की घोषणा की, जिस पर मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर में इस पार्क के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। रायपुर में ''दिव्य कला मेला'' 16 अगस्त 2024 से 23 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा।

केन्द्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्य कला मेला, दिव्यांग भाई-बहनों के अद्वितीय कौशल और उद्यमशीलता का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। दिव्यांगजनों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने की है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि देश के सर्वांगीण विकास में दिव्यांगजनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना तब ही पूर्ण हो पाएगा, जब हमारे दिव्यांग भाई-बहन आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।

उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में संचालित राज्य संसाधन केंद्र (सीआरसी) के नए भवन बनने के बाद वहां दिव्यांगजनों के लिए डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में भी 'दिव्य कला मेला' का आयोजन किया जाएगा। इनके स्थान का निर्धारण मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले में लगभग 60 स्टॉल लगाए गए हैं। यहां आने वाले अन्य राज्यों के व्यंजनों का रसास्वादन कर सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को पहले अनेक नामों से संबोधित किया जाता था, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें दिव्यांगजन का नाम दिया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों की 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 श्रेणियां की गई है। शासकीय नौकरी में आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। शासकीय विद्यालयों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए सुगम भारत अभियान के तहत शासकीय भवनों, रेल्वे स्टेशनों, एयरपोर्ट में रैम्प तथा अलग शौचालय बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि दिव्य कला मेला ने दिव्यांगजन की रचनात्मकता, कौशल, और सृजनशीलता को एक मंच प्रदान किया गया है, जिससे वे अपने उत्पादों को देश-विदेश में प्रदर्शित कर सकें। उन्होंने कहा कि दिव्य कला मेला के पिछले सफल आयोजनों ने न सिर्फ दिव्यांगजन की भागीदारी को बढ़ावा दिया है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से दिव्य कला मेले में अधिक से अधिक संख्या में आने और दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों को देखने, परखने और खरीदने का आग्रह किया, ताकि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में सहायता मिले।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेला दिव्यांगजन के लिए न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि सामाजिक समरसता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजन को रियायती ऋण की स्वीकृति में हुई बाधाओं को दूर करते हुए, आज 25 लोगों को ऋण स्वीकृति पत्र जारी करना एक नई शुरुआत का प्रतीक है।

एनडीएफडीसी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने दिव्यांगजन के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए इस मेले का आयोजन एक ऐतिहासिक अवसर है। जिसमें 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के दिव्यांग उद्यमी और कलाकार अपने उत्पाद लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहे हैं।

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजन यदि कुछ नया सोचते है तो राज्य सरकार उन्हें अपने सपने को साकार करने के लिए प्रोत्साहन देगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 12 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री वीरेन्द्र कुमार से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन पार्क का निर्माण कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति की नहीं प्रोत्साहन की जरूरत है। उनकी प्रतिभा को सामने लाने और आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में आकांक्षा इंस्टिट्यूट के दिव्यांग विद्यार्थियों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों को पुरूस्कार स्वरूप 51 हजार रूपए की राशि का चेक प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने 4 दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्रायसाइकिल तथा एक दिव्यांग को ट्रायसाइकिल तथा 11 दिव्यांग हितग्राहियों को ट्रेक्टर, ई-रिक्शा क्रय, ट्रेक्टर ट्रॉली, मेडिकल स्टोर, रेडीमेट गारमेंट, किराया दुकान, सेंट्रींग प्लेट, टेंट हाउस व्यवसाय के लिए ऋण राशि के चेक वितरित किए।

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण किया। मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों सहित अनेक राज्यों के उत्पादों हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई का काम, राखियां, पैकेज्ड फूड, गृह सज्जा और जीवन शैली से संबंधित वस्तुएं, कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद, खिलौने, पेंटिंग और उपहार, व्यक्तिगत सहायक उपकरण, आभूषण, क्लच वेग आदि उत्पाद प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) द्वारा रायपुर में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के डीडीजी, किशोर बाबूराव सुरवाडे ने स्वागत भाषण दिया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के सीएमडी, नवीन शाह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

कांग्रेस में अपराधियों की धाक इतनी बढ़ गई है कि वे कांग्रेस के फैसलों में सीधी दखल रखने लगे हैं

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल के उस बयान को कांग्रेस में मचे घमासान का एक और प्रमाण बताया है, जिसमें शुक्ल ने कहा है कि कांग्रेस में आपराधिक तत्व सक्रिय हैं और इन्हें बड़े नेताओं की शह प्राप्त है और जिसके कारण चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। शुक्ल का यह बयान बताता है कि कांग्रेस में अब अपराधियों की घुसपैठ हो गई है और अपराधी अब न केवल कांग्रेस के झंडाबरदार हो गए हैं, अपितु कांग्रेस में उनकी धाक इतनी बढ़ गई है कि वे प्रदेश कांग्रेस के फैसलों में सीधी दखल रखने लगे हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि अपराधियों के इसी दबदबे से कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी में खुद को उपेक्षित समझकर किनारे हो गए और कांग्रेस को पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने वाले, गोठान, कोयला, शराब, 18 लाख गरीबों का आवास घोटाला के रूप में छत्तीसगढ़ को लुटते रहे। घोटाले बाद घोटाले में शामिल जो कांग्रेस के नेता थे उनकी शिकायत सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक हुई लेकिन किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मोहन मरकाम ने विधानसभा सत्र में कहा था कि डीएमएफ में घोटाला हो रहा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने स्पष्ट कहा था कि कलेक्टर रानू साहू कमीशन जहां मिलता है वही काम करती है। इसके बावजूद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई कार्यवाही किसी पर नहीं की आखिर यह लुटेरे किसके शह पर कांग्रेस में राज कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि भाजपा शुरू से यह बात कहती रही है कि कांग्रेस और अपराधियों में खूब भाईचारा निभाया जा रहा है। कांग्रेस की भूपेश सरकार में तो हालात ये हो गए थे कि यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि कांग्रेस और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, या फिर अपराधियों का राजनीति और कांग्रेसीकरण हो गया है।

कांग्रेस के शासनकाल में तमाम श्रेणी के अनेक अपराधों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता और उनके परिजन-शुभचिंतक सीधे तौर पर शामिल थे या फिर अपराधों को अंजाम देने के बाद राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने हेतु अपराधियों के सामने कांग्रेस ही शरणस्थली बन गई थी। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश से लेकर केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व शुक्ल के इस बड़े आरोप को लेकर दुविधा में पड़ गया है, क्योंकि शुक्ल अविभाजित मध्यप्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे स्व. पं. श्यामाचरण शुक्ल के पुत्र और अनेक वर्षों तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे स्व. पं. विद्याचरण शुक्ल के भतीजे हैं और स्वयं अमितेश शुक्ल कांग्रेस में अपना बड़ा राजनीतिक कद रखते हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने यह भी सवाल किया कि कांग्रेस शासनकाल में महादेव सट्टा की वसूली के लिये दुबई से हत्या की सुपारी देकर ,हत्या करायी थी,अंतराष्ट्रीय अपराधगढ बन गया था।ये अपराधी तत्व कांग्रेस और उसकी भूपेश सरकार का राजनीतिक संरक्षण हासिल करके पूरे प्रदेश में माफियागिरी करके सरेआम गुंडागर्दी कर रहे थे, आतंक फैलाकर जंगलराज कायम करके लोगों का साँसें लेना दूभर कर रहे थे।

जातीय विद्वेष फैलाने के षड्यंत्र में जाँच की आँच और नक्सली-उन्मूलन की कार्रवाई से बेचैन कांग्रेस आज कानून-व्यवस्था का प्रलाप मचाकर षड्यंत्रपूर्वक झूठा नैरेटिव चला रही है, और भूपेश सरकार के नाकारापन की सच्चाई देखने से मुँह चुराकर आज कानून-व्यवस्था का अनर्गल प्रलाप कर रही है। ऐसे मे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता शुक्ल का यह बयान कांग्रेस और भूपेश सरकार के कामकाज को 'आईना' दिखाने वाला साबित होगा।

मूणत की अगुवाई में रविवार को निकलेगी विशाल कांवड़ यात्रा

रायपुर। सार्वजनिक तथा भक्तिमय आयोजनों को भव्य और गरिमामयी स्वरूप देने के मामले में स्थापित हो चुके रायपुर पश्चिम के दिग्गज भाजपा विधायक राजेश मूणत रविवार को हनुमान मंदिर गुढ़ियारी से सुबह 9 बजे विशाल कांवड़ यात्रा निकालने जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त पूर्व मंत्री मूणत हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ लेकर गुढ़ियारी से महादेवघाट जाएंगे, जहां बाबा हटकेश्वरनाथ को जलाभिषेक किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को भव्यता देने के लिए बाबा महाकाल के शहर उज्जैन से लेकर उत्तरप्रदेश तक के डमरूधारी तथा अघोरी नर्तकों की टोलियां, संबलपुर के बाहुबलि कटप्पा के वेश में संगीत दत के साथ छत्तीसगढ़ के पंथी, आदिवासी और राउत नाचा की नर्तक टोलियां भी साथ चलेंगी। गुढ़ियारी से महादेवघाट तक पूरे मार्ग में पुष्पवर्षा और भंडारे चलते रहेंगे। विशाल कांवड़ यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा स्पीकर डा. रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व गवर्नर रमेश बैस समेत कई विधायक शामिल होंगे। पूर्व मंत्री मूणत ने राजधानी के सभी शिवभक्तों को कांवड़ यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। वरिष्ठ विधायक मूणत ने 14 अगस्त को विशाल तिरंगा बाइक यात्रा का सफल आयोजन किया था और इस बार इसे भी भव्य स्वरूप देने में कामयाब हुए थे। अब उन्होंने 18 अगस्त, रविवार को विशाल कांवड़ यात्रा की तैयारी लगभग पूरी कर ली है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

टिकट दिलाने के नाम पर हुआ 60 लाख का खेल

रायपुर. पीसीसी चीफ दीपक बैज के बंगले में बिना रोक-टोक आने-जाने वाले एक कांग्रेसी नेता इन दिनों खूब सुर्खियों में है. सुर्खियों में इसलिए क्योंकि पीसीसी चीफ के करीबी होने का फायदा उठाकर उसने विधानसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर कई लोगों से जमकर वसूली की. लेकिन अब उसकी करतूतें खुलने लगी है और सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि इस मामले में पिथौरा थाने में एक एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन साहब के आदेश के बाद ये मामला गुपचुप तरीके से काम कर रहा है. अब ये साहब कौन है ये सूत्र ने स्पष्ट नहीं बताया. पीसीसी चीफ दीपक बैज के बंगले में पथौरा के कोई 'सिन्हा' आना-जाना करते थे. जो बेहद करीबी थे. उक्त 'सिन्हा' ने विभिन्न लोगों के माध्यम से टिकट दिलाने के लिए कई कांग्रेसी नेताओं से पैसे लिए. लल्लूराम के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक ये राशि 60 से 80 लाख रूपए के बीच है. इस मामले में पिथौरा थाने में एक एफआईआर भी हुई है. जिसके बाद विराट नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने पैसे लेन-देन की बात स्वीकार भी कर ली है. उक्त आरोपी भानपुरी (बस्तर) का रहने वाला बताया जा रहा है. जिन-जिन नेताओं से पैसे लिए गए है उन्हें पैसे लौटा देने की बात कही गई है. इसलिए इस मामले में कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है. इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज से भी बातचीत की. पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी दुर्ग में हूं और इस मामले में मैं आपसे अपने बंगले में मिलकर बात करता हूं.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट

रायपुर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने एक बार फिर से भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल पर तीखा हमला बोला है। डहरिया ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल अंदर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, लेकिन बाहर से उन्हें भाजपा प्रत्याशी का साथ देना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्रवाल मंत्री पद से हटाए जाने से नाराज हैं और इस कारण से वे कांग्रेस का समर्थन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने सांसद अग्रवाल के कांग्रेस में गुटबाजी होने के बयान का पलटवार भी किया। पूर्व मंत्री डहरिया ने सांसद अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई योग्य नेता हैं और पार्टी हाईकमान समय पर निर्णय लेती है, जिसे सभी नेता मानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हो रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि योग्य लोगों के विषय में चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन पद की मांग करने से कुछ नहीं मिलता, इसका निर्णय हाईकमान ही करेगा। बलौदाबाजार हिंसा मामले में डॉ. डहरिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोगों को निशाना बनाकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

बेटी के जन्म पर एफडी कराएगी नगर निगम

रायपुर. रायपुर नगर निगम एमआईसी में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. जिसके तहत शासकीय अस्पताल में जन्म लेने वाली बीपीएल परिवार की बेटी के नाम से फिक्स डिपाजिट कराने की योजना है. इसमें बेटी को 18 साल की उम्र के बाद लाखों रूपए मिलने वाले है. रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि नगर निगम शासकीय अस्पताल में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर 20 हजार रूपए डिपाजिट करने की तैयारी में है. इसके लिए अभी निगम के अधिकारी और एमआईसी सदस्यों के अलावा बैंक के लोगों से भी बातचीत करने की तैयारी है. महापौर ने कहा कि बैंक के लोगों से बातचीत करने के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न जिस योजना के तहत मिलेगा वो बेटियों को दिलाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो शैक्षणिक टूर पर वो पार्षदों के साथ गए थे वहां से उन्हें ये योजना का ख्याल आया. उन्होंने कहा कि वे भी बेटियों के पिता है, इसलिए उन्हें ये एहसास है कि बेटियों के पिता की क्या जिम्मेदारी होती है और एक गरीब परिवार के लिए ये राशि कितना महत्वपूर्ण है. इस मामले में अंतिम फैसला एमआईसी की बैठक के बाद ही आना है. हालांकि इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है

कांग्रेस ने फिर उठाया नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का मुद्दा

रायपुर। कांग्रेस ने बस्तर के नगरनार स्थित एनएमडीसी के स्टील प्लांट के निजीकरण का मुद्दा फिर से उठाया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एनएमडीसी स्टील प्लांट का वित्त वर्ष 2025 के अंत तक निजीकरण तय बताया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया 'एक्स' में किए अपने एक पोस्ट लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनाव के दौरान बस्तर की जनता से किए गए वादे की याद दिलाते हुए लिखा है कि 'क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा!' जयराम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ऐसा लगता है कि बस्तर के एनएमडीसी स्टील प्लांट का वित्त वर्ष 2025 के अंत से पहले निजीकरण तय है. उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, 3 अक्टूबर 2023 को नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने स्टील प्लांट का उद्घाटन किया था. इस अवसर पर उन्होंने वादा किया था कि नगरनार स्टील प्लांट बस्तर के लोगों की संपत्ति है, और उनकी ही रहेगी. 19 अक्टूबर 2023 को स्वयंभू चाणक्य ने प्रधानमंत्री के वादे को दोहराते हुए कहा कि एनएमडीसी के बस्तर स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं किया जाएगा.

इलाज कराने के बहाने बहु कराया गया गर्भपात

मुंगेली. जिला मुख्यालय स्थित स्वास्तिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि उनकी जानकारी के बगैर इस अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका गर्भपात कर दिया. यही नही महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए यह भी कहा है कि उनके सास-ससुर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बहाने धोखा देकर उनका अबॉर्शन करवा गया है. महिला ने एसपी से उचित कार्रवाई कर न्याय की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल एडिशनल एसपी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. गिरिजाशंकर जायसवाल से न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित महिला खुशबू ने शिकायत दर्ज कराई है कि 28 जुलाई को मेरी सास मोतीम बाई और ससुर सीताराम गबेल ने मुझे स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बहाने मुंगेली चलने को कहा, इस पर मैंने कहा कि तीन-चार महीने के प्रेगनेंसी में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है. इसके बावजूद उन्होंन मुझे जबरन चेकअप के बहाने मुंगेली के स्वास्तिक हेल्थ केयर प्राईवेट हॉस्पिटल ले गए. पीड़िता ने बताया कि अस्पताल में पहले मुझे एक किनारे में बैठा दिया गया, मेरे सास व ससुर हॉस्पिटल के डॉक्टर से क्या बात किये मुझे नहीं मालूम. इसके बाद मुझे कुछ इन्जेशन और दवाइयां दी गई और फिर दूसरे दिन डॉक्टरों ने मुझसे बिना पूछे-बताए मेरा अबॉर्शन कर दिया और मुझे भनक भी नहीं लगने दी. मुझे अबॉर्शन का पता तब चला, जब मुझे ब्लीडींग होने लगी.

किसानों को पावर रिपर, तेलघानी यंत्र, स्पेयर का किया वितरण,

फसलों पर जीवित जीवों के हानिकारक प्रभाव को कम करने की दिशा में बेहतर काम कर रहा है राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान : डॉ. रमन सिंह

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज राजधानी रायपुर के समीप ग्राम बरौंडा में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित लाभार्थी किसान सम्मेलन के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित अतिथियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत प्रबंधन संस्थान परिसर में रूद्राक्ष का पौधा रोपण किया। डॉ सिंह ने इस दौरान प्रतीक स्वरूप पांच किसानों को कृषि यंत्र पावर रिपर, तेलघानी यंत्र, स्पेयर पंप का वितरण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लाभार्थी किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान साथी जैविक तनाव या बायोटिक स्ट्रेस जैसी गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाकर आधुनिक तकनीक के माध्यम से बेहतर कार्य कर रहे हैं। जैविक तनाव से तात्पर्य पौधे पर जीवित जीवों के हानिकारक प्रभाव से है, जिसमें कीड़े, कवक, बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कृषि में जैविक तनावों पर बुनियादी, रणनीतिक और अनुकूल अनुसंधान के माध्यम से छत्तीसगढ़ की भूमि से अधिक से अधिक अन्न उपार्जित कर प्रदेश में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर पायें इस उद्देश्य से 7 अक्टूबर, 2012 को इस संस्थान की यहां आधारशिला रखी गई थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संस्थान को 28 सितंबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया था। तब से लेकर अब तक इस संस्थान ने कई अनुसंधान किये, कृषि जगत में निरंतर छत्तीसगढ़

के किसानों की बेहतर फसल के लिए काम किये और ढेरों उपलब्धियां अर्जित की हैं। डॉ. सिंह ने बताया कि देश में जैविक स्ट्रेस से सालाना लगभग 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये की कृषि उपज का नुकसान होता है। भारत में जैविक स्ट्रैस के कारण सभी वस्तुओं में 30-35 प्रतिशत नुकसान होता है, वैश्विक स्तर पर, कीटों के कारण फसल उत्पादन का 10 से 28 प्रतिशत तक नुकसान होता है। एक ओर जहाँ अन्न के आभाव में बहुत सारे देश भुखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं तब दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में फसलों का नुकसान यह दिखाता है कि जैविक तनाव कृषि के लिए कितनी बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए इस संस्थान द्वारा रणनीति बनाकर और तकनीकी रूप से बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत कुल 3966 कृषक परिवारों और जनजातीय उप-योजना के तहत कुल 3324 कृषक परिवारों को शामिल किया गया है। प्रदेश के 13 जिलों जशपुर, रायगढ़, कांकेर, राजनांदगांव, बस्तर, महासमुंद, गरियाबंद, कोरबा, सरगुजा, धमतरी, बलौदाबाजार- भाटापारा, दुर्ग और रायपुर अंतर्गत कुल 333 गांवों को परियोजनाओं का लाभ दिया गया है। उन्होंने संस्थान द्वारा किसानों को समर्थन प्रदान करने के साथ ही अनुसंधान और युवाओं को कृषि के प्रति सजग बनाने की दिशा में किये जा रहे कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष किसानों को 6000 रूपये का आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है, तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 'पीएम किसान सम्मान निधि' की 17वीं किस्त जारी कर, किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रूपये अंतरित की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, पीकेवीवाई

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.